My Notes…..

राष्ट्रीय

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी छलांग

ठीक 43 वर्ष के बाद भारत ने विश्व शक्ति को फिर से चकित किया है। 17 मई को स्वदेशी परमाणु रिएक्टरों के सहारे 7000 मेगावाट बिजली बनाने का सरकार का फैसला भी दूसरे देशों को स्तब्ध करने वाला होगा। इस फैसले से भारत ने अमेरिका, रूस समेत तमाम विकसित देशों को यह साफ संकेत दिया है कि परमाणु ऊर्जा के लिए वह अब उनकी तकनीक पर ज्यादा दिनों तक निर्भर नहीं रहेगा। कैबिनेट ने 700-700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा के 10 रिएक्टर लगाने का फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपने बलबूते परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की क्षमता रखने वाले गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा।

क्या है

1. कैबिनेट के फैसलों के बारे में बिजली, कोयला, खनन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में घरेलू तकनीक पर आधारित प्रेस्राइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स (पीएचडब्लूआर) की दस यूनिटें लगाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई है।
2. इससे घरेलू उद्योगों को 70 हजार करोड़ रुपये के आर्डर मिलेंगे। यह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत को अत्याधुनिक तकनीक से संपन्न देशों की श्रेणी में ला देगा।गोयल ने बताया कि ये यूनिटें कहां लगाई जाएंगी और किन कंपनियों की तरफ से लगाई जाएंगी, इसका फैसला बाद में होगा। लेकिन इससे 33,400 लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर नौकरियां मिलेंगी।
3. इतना तय है कि इन संयंत्रों में सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ये संयंत्र लगाए जाएंगे।
4. कई मायने में एतिहासिक फैसलाकई मायने में सरकार का यह फैसला अहम है। हाल के दिनों में किसी भी देश की तरफ से परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की यह सबसे बड़ी योजना है। मोदी सरकार ने भारत के पहले परमाणु परीक्षण के ठीक 43 वर्षो बाद यह फैसला कर परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों, अधिकारियों व राजनेताओं को खास तरीके से धन्यवाद दिया है। इससे न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता में अड़ंगा डाल रहे देशों को संदेश दिया गया है।
5. अमेरिकी मदद से परमाणु बिजली संयंत्र लगाने का समझौता हो चुका है, लेकिन जमीन पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है।उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि सभी परमाणु इकाइयों को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत संभवतः वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे देश की मौजूदा परमाणु बिजली क्षमता को तीन गुणा किया जा सकेगा। भारत अभी परमाणु ऊर्जा से 6780 मेगावाट बिजली बनाता है और 6700 मेगावाट क्षमता पर काम चल रहा है। वर्ष 2021-22 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।
6. 17 मई को स्वीकृत परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा और वर्ष 2024-25 तक पूरा कर लिया जाएगा। वैसे वर्ष 2030 तक भारत परमाणु ऊर्जा से 35 हजार मेगावाट और वर्ष 2050 तक 60 हजार मेगावाट बिजली बनाने की योजना बना चुका है।

क्या है पीएचडब्लूआर

1. भारत में लगाए गए तमाम परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसी तकनीक के आधार पर लगाए गए हैं।
2. इसमें प्राकृतिक यूरेनियम को मुख्य ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जबकि हेवी वाटर को पूरी प्रक्रिया में एक संचालक या कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
3. भारत इस तकनीक से 700 मेगावाट क्षमता तक बिजली बनाने का संयंत्र लगा सकता है।

भूपेन हजारिका पुल का उद्घाटन

एनडीए सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में देश के सबसे लंबे ढोला-सदिया पुल का उद्घाटन किया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस पुल का नाम असम के मशहूर लोकगायक भूपेन हजारिका के नाम पर रखने का एलान किया।

क्या है

1. भूपेन हजारिका पूरी जिंदगी ब्रह्मपुत्र नदी का गुणगान करते रहे। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को उनके योगदान के बारे में याद दिलाते रहने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है।
2. भूपेन हजारिका सिर्फ बेहतरीन गायक ही नहीं, बल्कि संगीतकार, गीतकार, कवि और फिल्मकार भी थे। उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के से लेकर पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार से नवाजा चुका है।
3. यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक लोहित नदी के ऊपर बना है, जिसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला में और दूसरा छोर असम के सदिया में पड़ता है, जहां भूपेन हजारिका का जन्म हुआ था।

देश में पहली बार जीका वायरस ने दी दस्तक

देश में पहली बार जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ) ने गुजरात के अहमदाबाद में जीका वायरस के तीन मामलों की पुष्टि की है। तीनों ही मरीज अहमदाबाद के बापूनगर के बताए जा रहे हैं। मरीजों में एक 22 वर्षीय गर्भवती महिला भी है। महिला का इसी साल ब्लड सैंपल लिया गया था।

क्या है

1. डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदाबाद के बीज.जे. मेडिकल कॉलेज (ठश्रडब) ने 10 से 16 फरवरी 1016 के बीच 93 ब्लड सैंपल इकट्ठे किए थे। इनमें से एक 64 साल के बुजुर्ग में जीका वाइरस पाए गए।
2. वहीं 34 वर्षीय एक महिला के ब्लड सैंपल में भी जीका वाइरस की पुष्टि हुई है। महिला ने बीते साल नवंबर में बीजेएमसी में ही एक बच्चे को जन्म दिया था। उस समय महिला का ब्लड सैंपल लिया गया था जिसमें जीका वाइरस पाए जाने की पुष्टि हुई है।
3. जीका वायरस ने निपटने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स भी गठित की गई है।
4. टास्क फोर्स में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव और स्वास्थ्य शोध विभाग के सचिव भी होंगे। यह टीम जीका के बढ़ते मामलों पर नजर रखेगी।

क्या है जीका वायरस

1. जीका वायरस 1940 में सबसे पहले युगांडा में पाया गया था.
2. बाद में यह महामारी की तरह अफ्रीका के कई हिस्सों में फैला गया.
3. अफ्रीका के बाद ये दक्षिण प्रशांत और एशिया के कुछ देशों में भी फैला.
4. कुछ समय पहले यह लैटिन अमेरिका पहुंचा है.
5. साल 2016 की शुरुआत में यह ब्राजील में दिखा.
6. डॉक्टरों का मानना है कि 2014 के फुटबॉल विश्व कप के दौरान ये वायरस एशिया या दक्षिण प्रशांत से आया होगा.

डीप ओशन मिशन

केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जनवरी 2018 में 'डीप ओशन मिशन' का शुभारंभ करने के लिए तैयार है। यह मिशन समुद्र अनुसंधान क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति को बेहतर करेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव श्री एम. राजीवन ने इस मिशन को शुरू करने की घोषणा की। श्री राजीवन ने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन के दौरान इस मिशन को शुरू करने की घोषणा की। भारत के अग्रणी निवेशक के दर्जे के तीन दशक ख उपलब्धियां एवं आगे का रास्ता विषय पर आयोजित कार्यशाला में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य श्री एम

एस नागर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. वीएसएन मूर्थि भी मौजूद थे। इस अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव श्री राजीवन ने कहा कि भारत ने समुद्र अनुसंधान के क्षेत्र में काफी उपलब्धि हासिल कर ली है, मगर अभी भी इस दिशा में एक लंबी दूरी तय करना बाकी है।

क्या है

1. भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे गहरे समुद्र में खनन अन्वेषण के लिए पर्याप्त क्षेत्र दिया गया था। वर्ष 1987 में भारत को केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन में पॉलिमेटालिक नोड्यूल्स में अन्वेषण का मौका मिला था।
2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय पॉलिमेटालिक मोड्यूल कार्यक्रम के अंतर्गत नोड्यूल खनन के लिए सीएसआईआर-एनआईओ द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन, सीएसआईआर-नेशनल मेटालर्जिकल लैबोरेट्री और सीएसआईआर- खनिज एवं धातु प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा धातु निष्कर्षण प्रक्रिया विकास और राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा खनन प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन किया गया।
3. संसाधन मूल्यांकन के आधार पर, भारत के पास लगभग 100 मिलियन टन सामरिक धातुओं जैसे कॉपर, निकेल, कोबाल्ट और मैंगनीज और आयरन के अनुमानित संसाधन के साथ लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है।

स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता को मंजूरी

सरकारी खरीद में स्थानीय उत्पादों की हिस्सेदारी बनाने के लिए सरकार ने खरीद की नई नीति बनायी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति के मसौदे पर मुहर लगा दी। इसके तहत अब जिन उत्पादों की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर पर्याप्त है उसकी खरीद प्रक्रिया में केवल स्थानीय निर्माताओं को ही शामिल किया जाएगा। सरकार ने यह कदम मेक इन इंडिया की नीति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उठाया है। दूसरी तरफ सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

क्या है

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर की गई सरकारी खरीद की नई नीति में कहा गया है कि 50 लाख रुपये तक की वस्तुओं की सरकारी खरीद प्रक्रिया में केवल स्थानीय निर्माताओं को ही शामिल किया जाएगा।
2. इसके अलावा जिन उत्पादों के मामले में स्थानीय उत्पादन क्षमता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहां भी खरीद में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।
3. पचास लाख रुपये से अधिक अथवा ऐसे उत्पाद जिनमें स्थानीय क्षमता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, की सरकारी खरीद में अगर न्यूनतम बोली देने वाला स्थानीय निर्माता नहीं है तो स्थानीय निर्माता को 20 प्रतिशत के मार्जिन के साथ बोली मैच कराने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि ऑर्डर की मात्रा इतनी है कि उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है तो न्यूनतम बोली देने वाले निर्माता के साथ स्थानीय निर्माता को आधा आधा आर्डर दिया जाएगा।
4. औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) के तहत एक स्थायी समिति इस नीति के अमल की निगरानी करेगी। यदि समिति को कुछ सुझाव देने की आवश्यकता होगी तो वह संबंधित मंत्रालयों को सीधे सिफारिश कर सकेगी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 'दरवाजा बंद' अभियान

देशभर के गांवों में शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय 30 मई 2017 से 'दरवाजा बन्द' नामक एक नए अभियान की शुरुआत करेगा। मुंबई में आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन अभियान का नेतृत्व करेंगे। केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़नवीस, केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर और अन्य गणमान्य लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान में योगदान देने वाले विभिन्न राज्यों के चैंपियनों को सम्मानित भी किया जाएगा।

क्या है

1. इस अभियान को विश्व बैंक से समर्थन प्राप्त है और इसकी औपचारिक शुरुआत होने के तुरंत बाद इसे देशभर में चलाया जाएगा। जिन लोगों के घरों में शौचालय है, इसके बावदूद वे इसका इस्तेमाल नहीं करते, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इस अभियान को तैयार किया गया है।
2. इस अभियान की एक विशेषता प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का इसमें शामिल होना है। अनुष्का महिलाओं को इस मुद्दे के बारे में आगे बढ़कर आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेंगी।
3. श्री बच्चन स्वच्छ भारत मिशन के बड़े समर्थक रहे हैं और वर्तमान में जारी स्वच्छ भारत अभियान के साथ भी वह जुड़े हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के केन्द्र में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना शामिल है, जिसके लिए देशभर में सूचना-शिक्षा-संचार (आईईसी) अभियान चलाए जा रहे हैं। संचार अभियानों को केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर अपनाया गया है ताकि शौचालयों के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ाने के क्रम में जागरूकता फैलाई जा सके। दरअसल इस अभियान का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण करना भी है।

पोखरण का वो पहला परीक्षण

18 मई 1974... ये वो तारीख है जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। हिन्दुस्तान ने इस दिन परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को हिला दिया था। पोखरण में हुए इस परीक्षण के बाद भारत दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़ा हो गया। उस वक्त भारत से पहले इस तरह का परमाणु परीक्षण सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थायी देशों ने ही किया था। इस ऑपरेशन में नाम रका गया था- स्माइलिंग बुद्धा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था पहला पोखरण परीक्षण.

क्या है

1. हालांकि, गोपनीय तरीके से पोखरण में किए गए पहले परमाणु परीक्षण के लिए रखे गए इस नाम की अलग वजह है। पहला कारण तो यह कि जिस दिन यह परीक्षण किया गया उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी और दूसरी वजह ये कि भारत इस परीक्षण के जरिए दुनिया में शांति का संदेश देना चाहता था।
2. श्पोखरण में भारत की तरफ से किए गए पहले परीक्षण के बाद जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया तो वहीं दूसरी तरफ बौखलाए अमेरिकी ने भारत को परमाणु सामग्री और ईंधन की आपूर्ति पर रोक लगा दी।
3. इंदिरा गांधी ने साल 1972 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बीएआरसी) का दौरा करते हुए वहां के वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण के लिए संयंत्र बनाने की इजाजत दी थी,लेकिन गांधी की ये इजाजत मौखिक थी। परीक्षण के दिन से पहले तक इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया था। यहां तक कि अमेरिका को भी इसकी कोई जानकरी नहीं लग पाई। इस गोपनीय प्रोजेक्ट पर काफी वक्त से एक पूरी टीम काम कर रही थी।
4. 1967 से लेकर 1974 तक 75 वैज्ञानिक और इंजीनियरों की टीम ने सात साल कड़ी मेहनत की। इस प्रोजेक्ट की कमान बीएआरसी के निदेशक डॉ. राजा रमन्ना थे।
5. रमन्ना की टीम में उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे जिन्होंने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की टीम का नेतृत्व किया था. इस प्रोजेक्ट का कोड वर्ड 'बुद्धा इज स्माइलिंग' था।

जाधव केस में पाक को झटका

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस ना देने को विएना संधि का उल्लंघन करार देते हुए फिलहाल जाधव की फांसी पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है।

इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण जाधव पर अपने फैसले में यह बातें कही

1. भारत और पाकिस्तान दोनों इस बात से सहमत हैं कि कुलभूषण जाधव भारत का नागरिक है
2. कुलभूषण जाधव की गिरफ्तार का मसला पूरी तरह से विवादित है
3. विएना संधि के मुताबिक, भारत को कांसुलर एक्सेस मिलनी दी जानी चाहिए
4. अदालत ने माना कि प्रथमदृष्टया यह केस में उनके सुनावाई के अधिकार में आता है।
5. पाकिस्तान की तरफ से जो दलीलें अदालत के सामने रखी गई वह भारत के दावे को नाकाफी बताने में असफल रहा। विएना संधि के तहत भारत ने जो बातें रखी उसे अंतरराष्ट्रीय अदालत ने स्वीकार किया।
6. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कहा कि पाकिस्तान इस बात को सुनिश्चित करें कि अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को फांसी पर ना लटकाया जाए।

कोर्ट में चली सुनवाई से जुड़ी अहम बातें

1. पाकिस्तान तब तक फांसी की सजा पर अमल न करे, जब तक आईसीजे इस पर अपना आखिरी फैसला नहीं दे देता।
2. इंटरनैशनल कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान जाधव की सुरक्षा सुनिश्चित करे और किसी दुर्भावना के साथ काम न करे।
3. इंटरनैशल कोर्ट ने माना कि जाधव मामला विएना संधि के तहत आता है। इसलिए भार को जाधव को काउंसलर मुहैया कराने का अधिकार है।
4. विएना संधि के अनुसार किसी दूसरे देश के नागरिक को बंदी बनाने वाले राष्ट्र के लिए उस देश के दूतावास के अधिकारियों को बंदी तक पहुंच स्थापित करने की मंजूरी देना जरूरी है।
5. इंटरनैशनल कोर्ट ने कहा कि कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी अभी भी विवादास्पद है।
6. इंटरनैशनल कोर्ट ने कहा कि विएना संधि का आर्टिकल 36 जाधव मामले में लागू नहीं हो सकता है।
7. इंटरनैशनल कोर्ट ने कहा कि विएना संधि के तहत भारत को जाधव तक राजनयिक पहुंच की इजाजत मिलनी चाहिए।
8. कुलभूषण जाधव मामला इंटरनैशनल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है।
9. इंटरनैशनल कोर्ट ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने विएना संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
10. इंटरनैशनल कोर्ट ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस बात से सहमत हैं कि कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक हैं।

पोटाश खनन करने वाला पहला राज्य

राजस्थान शीघ्र ही पोटाश खनन करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। राजस्थान के बीकानेर में पोटाश के पर्याप्त भंडार मिले हैं। राज्य सरकार पिछले 5 सालों से प्रदेश में पोटाश भंडारों की खोज कर रही थी। 2013 में प्रदेश के 6 जिलों में खोज शुरू हुई थी। इनमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, चुरू, सिरोही और बांसवाड़ा शामिल हैं। बीकानेर में 600 मीटर गहराई तक पोटाश की खोज की गई और सफलता भी मिली। हालांकि अन्य जिलों में पोटाश खोजने में सफलता नहीं मिल सकी है।

क्या है

1. राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन रहा है जहां अच्छी क्वालिटी का पोटाश मिला है। बीकानेर में पर्याप्त मात्रा में पोटाश के भंडार मिले है। कुछ स्थानों पर ओर पोटाश होने के संकेत मिले है। अब पोटाश खनन के लिए लाइसेंस जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
2. इसके लिए मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रस्ताव पारित कराया जाएगा। खनन मंत्री का कहना है कि राजस्थान में पोटाश खनन होने से प्रदेश की मांग तो पूरी होगी ही, साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी पोटाश सप्लाई किया जाएगा।
3. खनन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि पोटाश मिलने से बीकानेर के किसानों की जमीनों की कीमत बढ़ेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वहीं सरकार को भी पोटाश के खनन से राजस्व मिलेगा।

आईटीए सूचकांक में भारत की रैंकिंग बेहतर

यूएनडब्ल्यूटीओ की परिभाषा के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन (आईटीए) में दो अवयव यथा विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) और अनिवासी देशवासियों का आगमन शामिल हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ ने अपने बैरोमीटर में आईटीए के लिहाज से विभिन्न देशों की रैंकिंग की है। भारत में अब तक केवल एफटीए के आंकड़ों का ही संकलन होता रहा है। हालांकि, भारत ने अब अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के आगमन के आंकड़ों का भी संकलन शुरू कर दिया है।

क्या है

1. वर्ष 2014 और वर्ष 2015 के दौरान क्रमशः 5.43 मिलियन तथा 5.26 मिलियन एनआरआई का आगमन हुआ। तद्नुसार, वर्ष 2014 और वर्ष 2015 के दौरान भारत में आईटीए की संख्या क्रमशः 13.11 मिलियन और 13.28 मिलियन आंकी गई। आईटीए का डेटा अब अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों के अनुरूप हो गया है, जिसमें एनआरआई और एफटीए दोनों का आगमन शामिल है।
2. इस आंकड़े को शामिल करने की बदौलत भारत की बेहतर रैंकिंग को अब यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जो वास्तविक एवं तुलनीय परिदृश्य को दर्शाती है। मार्च, 2017 के लिए नवीनतम यूएनडब्ल्यूटीओ बैरोमीटर के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के लिहाज से भारत की रैंकिंग 2014 और 2015 दोनों ही वर्षों में 24वीं रही, जबकि इन दोनों वर्षों में भारत की पिछली रैंकिंग क्रमशः 41 और 40 थी। इसे शामिल करने के बाद आईटीए में भारत की हिस्सेदारी भी वर्ष 2015 में 0.68 फीसदी (एफटीए पर आधारित) से बढ़कर 1.12 फीसदी हो गई है।
3. इससे पहले यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक (टीटीसीआई), 2017 में भी भारत की रैकिंग ने वर्ष 2015 के मुकाबले 12 पायदानों की छलांग लगाई थी। 2017 की टीटीसीआई रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 40वीं थी, जबकि वर्ष 2015, 2013 और 2011 में यह क्रमशः 52वीं, 65वीं और 68वीं थीं।

चितले समिति की सिफारिश

गंगा से गाद निकालने के लिए चितले समिति ने कई उपायों की सिफारिश की है, जिनमें गाद हटाने के कार्य के लिए वार्षिक गाद बजट से सबसे अधिक गाद हटाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, पहले हटाई गई तलछट/गाद के बारे में बताते हुए वार्षिक रिपोर्ट(रेत पंजीयन) तैयार करना और तलछट बजट बनाने का कार्य एक तकनीकी संस्थान को सौंपा जा सकता है, आकृति और बाढ़ प्रवाह का अध्ययन जिसमें सबसे अधिक गाद वाले स्थान से गाद हटाने की आवश्यकता का निरीक्षण और पुष्टि करने पर विचार किया जाना शामिल है।

क्या है

1. जल संसाधन नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय ने भीमगौड़ा(उत्तराखंड) से फरक्का(पश्चिम बंगाल) तक गंगा नदी की गाद निकालने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के वास्ते जुलाई 2016 में इस समिति का गठन किया था।
2. राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के विशेष सदस्य श्री माधव चितले को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। समिति के अन्य सदस्य जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव और केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे के निदेशक डॉक्टर मुकेश सिन्हा थे।
3. समिति से गाद और रेत खनन के बीच अंतर करने तथा पारिस्थितिकी और गंगा नदी के ई-प्रवाह के लिए गाद हटाने की आवश्यकता के बारे में बताने को कहा गया था।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि

1. भूमि कटाव, तलछट की सफाई और गाद अति जटिल घटनाएं हैं। तलछट प्रबंधन और नियंत्रण के लिए ‘सभी के लिए एक प्रकार’ का रूख अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह मामले अधिकतर क्षेत्र विशेष से जुड़े होते हैं।
2. भौगोलिक, नदी नियंत्रण संरचनाएं, मृदा और जल संरक्षण उपाय, वृक्षों की संख्या, नदी के तट की भूमि का उपयोग या उसमें फेरबदल (उदाहरण के लिए कृषि, खनन आदि) जैसे स्थानीय कारकों का नदी के तलछटी के भार पर काफी प्रभाव पड़ता है।

3. नदी नियंत्रण संरचनाओं (जैसे जलाशयों), मृदा संरक्षण उपायों और तलछट नियंत्रण कार्यक्रमों से गाद कम जमा हो सकती है, जबकि भूमि उपयोग में फेरबदल (उदाहरणार्थ वनस्पतियों की सफाई) या खेती जैसी गतिविधियों से गाद बढ़ सकती है। ऐसे में अंधाधुंध गाद हटाने से पारिस्थितिकी और पर्यावरण प्रवाह को अधिक नुकसान हो सकता है। इसलिये गाद हटाने के लिये दिशा निर्देश और बेहतर व्यापक सिद्धांत तैयार करने की आवश्यकता है, जिन्हें गाद हटाने की योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के समय ध्यान में रखा जाना चाहिये।
4. गंगा जैसी बड़ी नदियों में भूमि कटाव, तलछटी हटाने और गाद अति जटिल घटनाएं हैं और उनका अनुमान लगाने में अंर्तनिहित सीमाएं और अनिश्चितताएं होती हैं।
5. गुगल अर्थ के नक्शे पर मुख्य नदी गंगा की पैमाइश से पता चलता है कि विभिन्न पाट गतिशील संतुलन चरण में हैं। तलछटी मुख्यरूप से भीमगौड़ा बैराज के नीचे की ओर तथा गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों के संगम स्थल के नजदीक देखी गई है।
6. अत्यधिक गाद, बड़े पैमाने पर तलछट का जमाव और इसके नकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से घाघरा और उसके आगे संगम के नीचे की ओर पाया जाता है। घाघरा के संगम से आगे मैदानी इलाके में बाढ़ तेजी से बढ़ कर लगभग 12 से 15 मिलोमीटर तक फैल जाती है।
7. समिति का कहना है कि हालांकि गाद हटाने से नदी के जलीय प्रदर्शन में सुधार हो सकता है और इसलिए गाद हटाने के कार्य को न्याय संगत ठहराया जा सकता है, लेकिन नदी के पर्यावरण प्रवाह के सुधार में इसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। दूसरी ओर अंधाधुंध गाद हटाने या रेत खनन से नदी के ई-प्रवाह पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नदियों से तलछटी हटाने के महत्व को पहचानते हुए गाद हटाने का कार्य करते समय निम्नलिखित मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए:
8. नदी प्रणाली में गाद प्रवाह कम करने के लिए कृषि की बेहतर पद्धतियों और नदी तट की सुरक्षा/कटाव रोधी कार्यों के साथ जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्ध और जल विभाजक विकास कार्य आवश्यक हैं और इन्हें व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए।
9. कटाव, प्रवाह और तलछट का जमाव नदी के प्राकृतिक नियमन कार्य हैं और नदी का तलछट संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।
10. नदियों के प्रवाह में बिना किसी बाधा के बाढ़ के लिये पर्याप्त मैदान (पार्श्व संपर्क) प्रदान किया जाना चाहिए।
11. श्गाद हटानेश् की बजाय ष्गाद के लिये रास्ता देंष् की रणनीति अपनायी जानी चाहिए।

‘आस्ट्रेलिया से तीन प्रस्तर प्रतिमाओं की भारत वापसी’ संबंधी प्रदर्शनी

‘आस्ट्रेलिया से तीन प्रस्तर प्रतिमाओं की भारत वापसी’ संबंधी प्रदर्शनी नई दिल्ली के जनपथ में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में आरंभ हो गई है। इसका आयोजन आस्ट्रेलिया से तीन प्रस्तर प्रतिमाओं की सुरक्षित वापसी के संदर्भ में किया जा रहा है, जिनमें आसीन बुद्ध, बुद्ध के उपासक और देवी प्रत्यांगिरा की मूर्तियां शामिल हैं। इन प्रतिमाओं को नेशनल गैलरी ऑफ आस्ट्रेलिया ने 2007 में नैन्सी वाइनर, न्यूयॉर्क और 2005 में आर्ट ऑफ दी पास्ट, न्यूयॉर्क से खरीदी थीं। संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा ने कल (23.05.2017) प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। उन्होंने आस्ट्रेलिया के केनबरा में स्थिति नेशनल गैलरी ऑफ आस्ट्रेलिया में आयोजित एक विशेष समारोह में हिस्सा लिया था, जिसमें सीनेटर मित्च फीफील्ड ने औपचारिक रूप से भारत से चुराई गई और तस्करी द्वारा बाहर भेजी जाने वाली इन तीन प्राचीन कलाकृतियों को उन्हें सौंपा था; इन कलाकृतियों को बाद में नेशनल गैलरी ऑफ आस्ट्रेलिया ने खरीद लिया था। इसके पहले सितंबर, 2014 में जब आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए थे, तो उस समय भी आस्ट्रेलिया की सरकार ने ‘नृत्य करते शिव’ प्रतिमा वापस की थी। यह प्रदर्शनी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन देश से चुराई जाने वाली तीन दुर्लभ प्रतिमाओं की वापसी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है।

1. बुद्ध के उपासकों की प्रतिमा: (सातवाहन, पहली शताब्दी बीसीई से दूसरी शताब्दी सीई, आन्ध्र प्रदेश, दक्षिण भारत, चूना पत्थर, आकार : 96.5◦106.7◦12.7 सेमी.)। इस प्रस्तर कला में एक स्तूप है (संभवत: ड्रम स्लेब) जो चूना पत्थर का बना है। इस पैनल में कुछ बौद्ध प्रतीकों की उपासना दिखाई गई है, जो संभवत: चक्रस्तंभ या बोधिवृक्ष है, लेकिन ऊपर का हिस्सा टूट जाने के कारण स्पष्ट नहीं है। यह एक सिंहासन पर रखा हुआ है, जिसके नीचे बुद्ध-पद नजर आ रहे हैं। मध्य में उपासक जोड़े दोनों तरफ बने हैं, जो खड़े हुए हैं। दोनों तरफ पुरुष उपासक हैं और उनके पीछे स्त्री उपासकों की

प्रतिमाएं हैं। उनके हाथों में फूल या फूलों के हार बनाए गए हैं। इस मूर्ति को चन्द्रवरम (जिला प्रकाशम), आन्ध्र प्रदेश में बौधस्तूप की 1970 के दशक में खुदाई के दौरान निकाला गया था।

2. विशाल आभामंडल सहित आसीन बुद्धः (कुषाण, दूसरी शताब्दी सीई, महोली, मथुरा, उत्तर प्रदेश, चित्तीदार लाल बलुई पत्थर, आकार : 129.5◦101.5◦30.5 सेमी.)। इस मूर्ति में बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं। इसमें बुद्ध को एकांशिक संघति (एक कंधे पर दुप्प्ट्टा जो कई तहों में है) धारण किये हुए दिखाया गया है। कपड़े को पारदर्शी दिखाया गया है और उसके बीच से नाभिस्थल स्पष्ट दिखता है। मूर्ति का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा बायां हाथ जंघा पर रखा है। विशाल आभामंडल तराश कर बनाया गया है। इसमें हस्ती नख कमर के ऊपर स्थित है। बुद्ध को उर्ण, प्रलंब कर्ण (लटका हुआ कान का निचला हिस्सा), उष्णिशा और उनके मुख पर ध्यान की आभा दिख रही है।

3. खड़ी मुद्रा में प्रत्यांगिराः (चोल, 13वीं शताब्दी सीई, तमिलनाडु, दक्षिण भारत, सलेटी रंग का ग्रेनाइट पत्थर, आकार : 125. 1◦55.9◦30.5 सेमी.)। संरक्षण के अपने सर्वोच्च कर्तव्य को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था, जिसमें उन्होंने मानव शरीर और शेर के मुख का रूप धारण किया था। उन्होंने दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यपु का वध किया था, जो पाप का प्रतीक था। इस मूर्ति में तांत्रिक उपास्य को दिखाया गया है जो भगवान नरसिंह का स्त्री पक्ष है। इसे नरसिंही के रूप में भी जाना जाता है। इनका साधनामाला के लिए भी आह्वान किया जाता है। यह देवी प्रालंबपदित मुद्रा में खड़ी हैं। उनका मुख गरजते हुए क्रुद्ध शेर के रूप में है और शरीर स्त्री का है। उनके सिर से ज्वाला निकल रही है। उनके दांये हाथ में त्रिशूल और डमरू है। यह प्रत्यांगिरा की मूर्ति है, जिसे शैव मत के अनुसार भैरवी का रूप माना जाता है। चोरी होने से पहले इस मूर्ति की उपासना चेन्नई के निकट स्थित वृद्धाचलम मंदिर में की जाती थी।

देश का सबसे घनी आबादी वाला शहर

प्रतियोगी परीक्षाओं का हब माना जा वाला शहर, औद्योगिक पावरहाउस, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कोटा। यह शहर एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल हाल ही में वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम लिस्ट में कोटा को विश्व का सांतवा सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर माना है। यहां पर प्रति वर्ग किमी 12100 की आबादी है। इस लिस्ट में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दूसरे स्थान पर है।

क्या है

1. वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका विश्व में सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है। यहां पर प्रति वर्ग किमी 44500 की आबादी है, जबकि मुंबई दूसरे स्थान पर है। मुंबई का घनत्व 31700 प्रति वर्ग किमी है।
2. कोलंबिया की राजधानी मेडेलिन (19700 प्रति वर्ग किमी) लिस्ट में तीसरे स्थान पर है, जबकि फिलीपिंस की राजधानी मनीला (14800 प्रति वर्ग किमी) चौथे, कासाब्लांका (14200 प्रति वर्ग किमी) पांचवे, लागोस (13300 प्रति वर्ग किमी) छठे, अबुजा (10500 प्रति वर्ग किमी) आठवें, सिंगापुर (10200 प्रति वर्ग किमी) नौवे और जकार्ता (9600 प्रति वर्ग किमी)दसवें स्थान पर है।
3. दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले शहरों में एशिया के छह शहर, तीन अफ्रीका के जबकि एक साउथ अमेरिका का है।

बोफोर्स के बाद पहली बार सेना को मिलीं तोपें

बोफोर्स सौदे के बाद पहली बार भारतीय सेना में तोपों को शामिल किया गया है। अमेरिका से 2 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोप भारत आ गई हैं। पाकिस्तान से लगी सीमा पर रक्षा तैयारियों के लिहाज से सेना के लिए यह अहम घटनाक्रम है।

क्या है

1. 1986 में बोफोर्स तोपों की खरीद के बाद इसके सौदे में दलाली के आरोपों ने भारतीय राजनीति में इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था कि नयी तोप खरीदने में करीब 3 दशक का वक्त लग गया। पिछले साल 26 जून को पहली बार जानकारी दी गई कि भारत 145 तोपों की खरीदारी करेगा।

2. नवंबर आते-आते भारत और अमेरिका के बीच इसके लिए डील हो गई। भारतीय सेना की खातिर 145 तोपों के लिए करार किया गया था। अमेरिकी कंपनी बीएई सिस्टम्स को इन तोपों को बनाने का जिम्मा सौंपा गया।
3. 17 मई को पहली 2 तोपें भारत आई। इन्हें जल्द राजस्थान के पोखरण भेजा जाएगा। वहां भारतीय गोला-बारूद से इनकी टेस्टिंग की जाएगी। इसके बाद 3 तोपों को सितंबर में लाने का प्लान है। फिर 2019 के मार्च से लेकर 2021 के जून के बीच हर महीने 5-5 तोपें आएंगी।
4. इन तोपों की रेंज 24 से 40 किलोमीटर है। इनके अलावा मेक इन इंडिया के तहत 100 वज्र तोपों के निर्माण पर भी हाल ही में करार हुआ है।

क्लीनिकल ट्रायल के लिए नए नियम बनाने में जुटा है भारत

भारत दवाओं के परीक्षण को लेकर जल्द ही नई नीति जारी करेगा। इसके तहत क्लीनिकल ट्रायल के लिए नए नियम तय किए जाएंगे। शीर्ष भारतीय अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य दवा निर्माण की नई परियोजनाओं के लिए अनुकूल महौल बनाना है।

क्या है

1. भारत के दवा महानियंत्रक जीएन सिंह के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय दल इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। बोस्टन में यूएस-इंडिया बायोफार्मा एंड हेल्थकेयर के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्लीनिकल ट्रायल को लेकर सरकार जल्द ही नए नियम-कायदे जारी करेगी। उम्मीद जताई कि इससे भारत में दवा क्षेत्र में शोध-अनुसंधान से जुड़ी नई परियोजनाएं आएंगी।
2. क्लीनिकल ट्रायल को लेकर विवाद और मामले के कोर्ट में लंबित होने से दवाओं के परीक्षण की रफ्तार बहुत कम गई है। यूएसए-इंडिया चौंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में सिंह ने कहा कि सभी पक्षकारों से सलाह-मशविरा कर नए नियम बनाए गए हैं। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव आरके वत्स ने कहा कि भारत सरकार दवा उद्योग के लिए आसान माहौल बनाने में जुटी है।

विदेशी तकनीक से मिशन 2020 पूरा करेगी कोल इंडिया

ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से आइआइटी आइएसएम में तैयार आधुनिक लैब में खान सुरक्षा संबंधी अध्ययन कार्य चालू है। मुनीडीह में खदान के अंदर चीनी मशीन के सफल ट्रायल से अफसरों का हौसला बुलंद है। वे कोल इंडिया की अन्य यूनिटों में भी इस तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं।

क्या है

1. मुनीडीह में पावर सपोर्ट लांगवाल माइनिंग (पीएसएलडब्ल्यू) के माध्यम से कोयला निकाला जा रहा है। वहां 15 सीम में कोयला खनन करने के लिए नई खदान खोली जा रही है।
2. इसमें जर्मन तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना है। बीसीसीएल ने हाई तकनीक के इस्तेमाल पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च करने की योजना बनाई है।
3. कोल इंडिया की एक दर्जन से अधिक भूमिगत खानों में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, चीन और जर्मनी की तकनीक अपनाई जा रही है।
4. भारत में 600-700 फीट नीचे तक कोयला खनन किया जा रहा है। जबकि विदेश में एक किमी की गहराई तक से कोयला निकाला जा रहा है।

सुखोई पर सस्पेंस कायम

असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरनेवाले आईएएफ विमान सुखोई 30 एमकेआई का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। 23 मई को दो पायलटों के साथ नियमित अभ्यास पर निकले इस विमान का संपर्क पौने दो घंटे बाद रेडार से टूट गया था। उसके बाद से लगातार इसकी तलाश की जा रही है। लेकिन, अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिल पायी है। भारतीय सेना के जवान बड़ी ही सरगर्मी के साथ इसकी तलाशी में जुटे हुए हैं।

क्या है

1. सुखोई 30 विमान की आखिरी लोकेशन चीन के बॉर्डर से सटे अरुणाचल प्रदेश के डौलासांग के इलाके में दर्ज की गई थी।
2. सुखोई को पहली बार साल 2002 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। सभी मौसम में मार करने में सक्षम और हवा से हवा और हवा से सतह में लक्ष्य को भेदने में बेहद कागरइ इस रूसी लड़ाकू विमान के पिछले सात सालों में जिस तरह आठवीं बार हादसे के शिकार होने की घटना सामने आ रही है उसके बाद इसने भारतीय वायुसेना के लिए चिंताएं बढ़ा कर रख दी है।
3. सुखोई विमान की अंतरराष्ट्रीय कीमत 358 करोड़ रूपये है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में फरवरी 2017 तक कुल 230 सुखोई का शामिल किया गया और इसे जंग के मैदान में आईएएफ के लिए 'बैक बोन' माना जाता है। लेकिन, सबसे बड़ी चिंता बार-बार हो रहे हादसों से बाद उठना लाजिमी है।
4. देश में पहला सुखोई विमान हादसा 30 अप्रैल 2009 को पोखरण में हुआ जबकि दूसरा सुखोई हादसा राजस्थान के ही हादाभासी जैसलमेर क्षेत्र में 30 नवंबर 2009 को हुआ। जबकि, तीसरा सुखाई 13 दिसम्बर 2011 को में पुणे में फिर चौथा सुखोई 19 फरवरी 2013 को आयरन फीस्ट के अभ्यास के दौरान क्रैश हुआ जो जोधपुर से उड़ा था।
5. पांचवां सुखोई अक्टूबर 2013 को पुणे में गिरा। उसके बाद छठा सुखोई 19 मई 2015 को असम में तेजपुर के पास गिरा। फिर 15 मार्च को एक सुखोई राजस्थान में गिरा और अब आठवां सुखाई विमान असम से उड़ान भरने के बाद गायब चल रहा है। सुखोई भारतीय वायुसेना के अंग्रिम पंक्ति का लड़ाकू जहाज है।
6. 1970 में करीब 50 विमान क्रैश हुए थे जबकि 1980 में इनकी संख्या 40 के असापास थी। जबकि, 1990 तक आते-आते वायुसेना के दुर्घटनास्त होने के मामलों में और कमी आयी ये संख्या 30 तक पहुंच गई। लेकिन, साल 2000 के बाद अब यह संख्या ग्यारह से बारह के बीच आ गई है।

एकीकृत विकास और समेकित वृद्धि के लिए केंद्रित सरकार

सरकार में कई अहम सरकारी योजनाएं जिनका लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और देश में बड़ा बदलाव आया, उनकी सफलता को दर्शाने के लिए दूरदर्शन ने 14 लघु फिल्मों का निर्माण किया है. ये फिल्म देशभर में जमीनी स्तर पर आए बदलाव को सफलतापूर्वक और विस्तार से बताने में सफल रही है। ये लघु फिल्में सभी दूरदर्शन केंद्रों पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में दिखाई जाएंगी जिसका लक्ष्य दूसरे लोगों को भी सरकारी योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए प्रेरित करना और इसकी जानकारी देना है। सूचना प्रसारण मंत्रालय सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए डव्क्प (मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया) यानि विकसित भारत निर्माण का एक उत्सव देशभर में मनाएगी जिसे मीडिया यूनिट के जरिए भी दिखाया जाएगा। दूरदर्शन की नई पहल फ्रीडिश में डीडी फ्री डिश सेवा देश में मौजूद सबसे बड़ी डीटीएच सेवा है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक 2 करोड़ 20 लाख परिवार तक इसकी पहुंच है। सरकार ने इसकी पहुंच और बढ़ाने के लिए डीडी डिटिएच बॉक्स को राज्य सरकारों के जरिए देश के सुदूर और आंतरिक इलाकों खासकर नक्सल पीड़ित इलाकों में मुफ्त में देने की योजना बनाई है।

लघु फिल्मों का विषय-वस्तु

1. मिशन इंद्रधनुष
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड
3. सबका साथ सबका विकास
4. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना
5. स्किल इंडिया
6. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
7. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
8. कौशल भारत कुशल भारत

9. प्रधानमंत्री जन धन योजना

अन्तरराष्ट्रीय

रास्ट्रीय

अंतरास्ट्रीय

पाक ने प्ब्श्र में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। 19 मई को पाकिस्तान सरकार ने आईसीजे में पुनर्विचार याचिका दायर की। इस याचिका में पाकिस्तान ने कोर्ट से छह हफ्ते में सुनवाई की मांग की है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, खावर कुरैशी फिर पाकिस्तान का पक्ष कोर्ट में रखेंगे।

क्या है

1. गौरतलब है कि आईसीजे ने अपने अंतरिम फैसले में पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह इस मामले पर अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा पर रोक लगा कर रखे।
2. जासूसी के आरोप में पाकिस्तान ने पिछले साल जाधव को गिरफ्तार किया था और एक सैन्य अदालत द्वारा उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है।
3. हालांकि इस सजा पर आईसीजे के रोक के फैसले के बाद पाकिस्तान सरकार को विरोधी पार्टियों व कानून विशेषज्ञों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इसके बाद ही वकीलों की नई टीम गठित करने का नया दांव खेला गया है।

अमेरिका का 146 साल पुराना रिंगलिंग सर्कस बंद

दुनिया के सबसे पुराने सर्कसों में शुमार रिंगलिंग ब्रदर्स एंड बर्नम एंड बेली सर्कस अब इतिहास बन गया है। 146 साल पुराने इस सर्कस को श्द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थश के तौर जाना जाता है। इसका अंतिम शो 21 मई को न्यूयॉर्क के लांग आइसलैंड के यूनियनडेल में हुआ। इस सर्कस की स्थापना 1871 में रिंगलिंग ब्रदर्स ने की थी।

क्या है

1. सर्कस का स्वामित्व रखने वाली फेल्ड इंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ केनेड फेल्ड ने कर्मचारियों से कहा कि आप सभी को अंतिम बार प्रस्तुति करते देखना दिल को छू लेने वाला है। अंतिम शो हाउसफुल रहा और इसका प्रसारण रिंगलिंग वेबसाइट पर भी किया गया।

2. फेल्ड ने इस साल जनवरी में सर्कस बंद करने की घोषणा की थी। उस समय फेल्ड ने कहा था कि अधिक लागत और टिकटों की बिक्री में गिरावट के चलते यह निर्णय लिया गया है।

3. इसका प्रमुख कारण दर्शकों की कमी और पशु अधिकार समूहों का दबाव भी माना गया था। इसी दबाव के चलते कंपनी ने पिछले साल शो से हाथियों को हटा दिया था।

4. हालांकि पेटा जैसे संगठनों के विरोध के बावजूद कंपनी ने अंतिम समय तक बाघ, शेर, घोड़े और ऊंट जैसे जानकारों का करतब दिखाना बंद नहीं किया।

दक्षिण सागर में भारत के सैन्य अभ्यास से बौखलाया चीन

सिंगापुर के साथ दक्षिण चीन सागर में भारत का नौसैनिक युद्धाभ्यास चीन को अखर रहा है। चीन के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करके भारत चीन के विवादित मसलों में पड़ने की अपनी नीति से दूर जा रहा है। दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा जताता है। हिस्सेदारी को लेकर फिलीपींस के पक्ष में आए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को भी उसने मानने से इन्कार कर दिया है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने कई स्थानों पर कृत्रिम द्वीप बनाकर चीन ने उनमें सैन्य तैनाती की है। उसी सागर के हिस्से में इन दिनों भारत व सिंगापुर की नौसेनाएं संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। अभ्यास के दौरान वहां पर पनडुब्बी रोधी उपकरण की तैनाती के भारत के उद्देश्य को भांपते हुए चीनी रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि यह हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बी के भ्रमण का जवाब जैसा है।

क्या है

1. यह बात चीनी सेना की रॉकेट फोर्स में काम कर चुके सोंग जोंगपिंग ने सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स से कही है। उनके अनुसार भारत ने दक्षिण चीन सागर मामले में चीन के खिलाफ कुछ न करने का वादा किया है लेकिन अब वह सैन्य अभ्यास करके उससे दूर जा रहा है। दोनों नौसेनाओं के बीच यह 24 वां वार्षिक अभ्यास है।

2. चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनीइंग ने हाल ही में कहा है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है कि कोई भी देश अपने पड़ोसी के हितों के खिलाफ काम न करे। जाहिर है उनका इशारा भारत-सिंगापुर के दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास की ओर था।

3. उल्लेखनीय है कि भारत और जापान द्वारा मिलकर तैयार किया जा रहा फ्रीडम कॉरीडोर भी चीन के न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट का जवाब माना जा रहा है। इससे भी चीन बौखलाया हुआ है।

4. दक्षिण एशिया मामलों के चीनी जानकार क्वैन फेंग इसे भारत का राजनीतिक निवेश मान रहे हैं।

5. ईरान के चाबहार पोर्ट, श्रीलंका त्रिंकोमाली पोर्ट और थाईलैंड-म्यांमार सीमा पर स्थित दावेई पोर्ट में भारत की रुचि को भी चीनी विशेषज्ञ इसी तौर पर देख रहे हैं।

नेपाली च्ड का इस्तीफा

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एएनआई के मुताबिक, वो कुछ देर में अपना इस्तीफा राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी को सौंपेंगे। इससे पहले उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला टाल दिया था, जिसके बाद काठमांडू में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रचंड ने अगले पीएम के तौर पर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा का रास्ता साफ करने के लिए यह फैसला लिया।

हालांकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के नेता के.पी. ओली ने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री स्थानीय चुनाव के मध्य इस्तीफा नहीं दे सकते और 14 जून को दूसरे चरण का चुनाव पूरा होने तक उन्हें पद पर बने रहना चाहिए।

क्या है

1. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के रूप में प्रचंड का दूसरा कार्यकाल था। 62 वर्षीय प्रचंड पिछले साल अगस्त में नेपाल के 39वें प्रधानमंत्री थे।
2. नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के समर्थन से प्रधानमंत्री बने प्रचंड ने नेकां के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसके मुताबिक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया।
3. प्रचंड और देउबा में इस बात की सहमति बनी थी कि दोनों फरवरी 2018 में संसदीय चुनाव होने तक बारी-बारी से प्रधानमंत्री पद संभालेंगे।
4. समझौते के अनुसार, प्रचंड को स्थानीय चुनाव होने तक पद पर रहना था, जबकि प्रांतीय और केंद्रीय स्तर के चुनाव देउबा के प्रधामंत्रित्व काल में होने थे।

स्पेन के साथ सात समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और स्पेन ने कुल सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें साइबर सुरक्षा और नागर विमानन क्षेत्र में तकनीकी मदद के करार भी शामिल हैं। पीएम मोदी की स्पेन के राष्ट्रपति मारियानो राजॉय से मोनक्लोआ पैलेस में कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने के बाद इन समझौतों पर साइन किये हैं।

क्या है

1. साथ ही दोनों पक्षों में सजा मिले लोगों के हस्तांतरण (ट्रांस्फर) और राजनायिक पासपोर्टधारकों के लिए वीजा छूट के संबंध में भी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
2. भारत और स्पेन ने अंग प्रत्यारोपण, साइबर सुरक्षा, अक्षय ऊर्जा, नागर विमानन क्षेत्र पर एमओयू पर साइन किए हैं। भारत के विदेश सेवा संस्थान और स्पेन की डिप्लोमैटिक अकादमी के बीच भी एक समझौता हुआ है।
3. वर्ष 1988 के बाद नरेंद्र मोदी स्पेन यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने स्पेन के राष्ट्रपति की सराहना करते हुए बताया कि राजॉय के नेतृत्व में देश में तेजी से आर्थिक सुधार हुए हैं।
4. भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूरोपीय संघ (ईयू) में स्पेन है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2016 में 5.27 अरब डॉलर रहा है।

दुनिया का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी

दुबई पुलिस ने दुनिया का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी श्रोबोकॉपश को पुलिसबल में शामिल कर लिया। यह रोबोकॉप जल्द ही दुबई के मॉल व पर्यटनस्थलों पर पुलिस बल के साथ गश्त करते दिखेगा। इतना ही नहीं, यह लोगों से हाथ भी मिलाएगा और उन्हें सलामी भी देगा। हाल में हुए गल्फ इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में

इसकी जानकारी दी गई। अधिकारियों का दावा है कि वर्ष 2030 तक करीब 25 फीसदी दुबई पुलिस रोबोकॉप पर निर्भर होगी।

ऐसा है रोबोकॉप

1. 5.5 फीट लंबाई और 100 किलो है वजन।
2. आठ घंटे तक कर सकता है काम
3. अरबी, अंग्रेजी के अलावा छह तरह की भाषा जानता है।
4. इसमें लगा सॉफ्टवेयर अपराधी की पहचान कर उसे पकड़कर पुलिस की मदद कर सकेगा।
5. इसके टैबलेट से लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह लोगों से जुर्माना भी वसूल कर सकता है।
6. इमोशन डिटेक्टर-यह किसी के भी दुख या सुख वाले भाव को पहचान सकता है और उन्हें खुश करने की कोशिश भी कर सकता है।
7. 1.5 मीटर की दूरी से हाथ के इशारे समझने में सक्षम।
8. इसमें लगा सिस्टम रोबोट को सोशल मीडिया व अन्य एप्स से जोड़े रखेगा।
9. इन-बिल्ट कैमरा-ताकि पुलिस स्टेशन पर सीधा प्रसारण किया जा सके।
10. लोगों की भावनाओं की भी आसानी से कर सकता है पहचान।

समलैंगिकों को शादी का अधिकार देने वाला पहला एशियाई देश

ताइवान की सबसे बड़ी अदालत ने समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता दे दी। इसके साथ ही ताइवान समलैंगिकों को शादी करने का कानूनी अधिकार देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा विवाह कानून लोगों के विवाह की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार, दोनों का उल्लंघन करते हैं। इनमें समलैंगिकों की शादी को अनुमति देने के लिए जरूरी संशोधन करने में दो वर्ष का समय लगेगा। ताइवान के मौजूदा कानून केवल पुरुष और महिला की शादी की इजाजत देते हैं लेकिन अदालत में इनकी वैधानिकता को चुनौती दी गयी जिसके बाद यह फैसला आया है।

क्या है

1. अदालत ने कहा, श्अगर समलैंगिकों की शादी से संबंधित कानून में दो वर्ष के भीतर संशोधन नहीं होता अथवा उसे लागू नहीं किया जाता है तो समान लिंग के लोगों का विवाह पंजीकरण प्रभावी माना जाएगा।श
2. अदालत के फैसले के बाद बड़ी संख्या में समलैंगिक रंगीन छतरियां लेकर ताइवान की संसद के बाहर एकत्रित हुए और जश्न मनाया।

3. समलैंगिक अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकताओं ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी वर्ष की कोशिश कामयाब हुई है। इस फैसले से समलैंगिकों की शादी को भी किसी भी महिला और पुरुष की शादी की तरह मान्यता मिलेगी।

4. गौरतलब है कि एशियाई देशों में शादी को लेकर रूढ़िवादी रवैये के कारण समलैंगिकों को न तो सामाजिक तौर पर स्वीकृति मिलती है और न ही उनके साथ रहने एवं शादी को लेकर कोई कानूनी प्रावधान है। ताइवान में विवाह कानून में संशोधन के साथ समलैंगिक जोड़ों को भी अन्य जोड़ों की तरह गोद लेने, संपत्ति और दूसरे मामलों में समान अधिकार हासिल हो जाएंगे।

द. कोरिया और अमेरिका ने सैन्य अभ्यास किया

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तमाम चेतावनियों को दरकिनार कर लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका को और बड़ा उपहार देंगे। प्योंगयांग ने किम की निगरानी में किए गए बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को सफल बताया है।

क्या है

1. स्कड श्रेणी की मिसाइल ह्वासांग की तुलना में यह नई मिसाइल उन्नत गाइडेंस सिस्टम से लैस है। वहीं दक्षिण कोरियाई सेना ने भी माना कि प्योंगयांग ने सोमवार को संशोधित स्कड श्रेणी की मिसाइल का परीक्षण किया था।

2. यह मिसाइल 450 किमी की दूरी तय करने के बाद पूर्वी समुद्री इलाके में गिरी थी। इस परीक्षण के बाद किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए और ज्यादा शक्तिशाली हथियार बनाएंगे। इसके जरिये अमेरिका को बड़ा शगिफ्ट पैकेजश देंगे।

छोटे देश का एक बड़ा अभियान

पूर्व सोवियत गणराज्य के छोटे से देश अर्मेनिया में एक वर्ष पहले शुरु किया गया दुनिया का सबसे बड़े परोपकारी अभियान लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। तकरीबन सौ वर्ष पहले ऑटोमन शासकों (मौजूदा तुर्की) ने अर्मेनिया मूल के 15 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। इसे जर्मनी में नाजियों की हत्या के बाद दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है लेकिन कई देश इसे अभी भी राजनीतिक वजहों से नरसंहार नहीं मानते। दो वर्ष पहले अर्मेनिया के तीन उद्योगपतियों ने औरोरा पुरस्कार का आगाज किया जो दुनिया के किसी भी कोने में उन लोगों या संगठनों को दिया जाता है जो बेहद दुरुह परिस्थितियों में गरीबों व वंचितों के उत्थान के लिए काम करते हैं।

क्या है

1. औरोरा प्राइज के एक संस्थापक रूबेन वर्दानयन ने बताया कि ऑटोमन गणराज्य ने भले ही 15 लाख अर्मेनियाई लोगों का कत्लेआम किया लेकिन उस दौरान भी पूरी दुनिया में हजारों ऐसे लोग थे जिन्होंने लाखों अर्मेनियाइयों की जान बचाई।

2. हम इस पुरस्कार के जरिए उन्हीं लोगों की हिम्मत व मानवीय वूसलों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी दुनिया भर में हजारों लोग व संगठन बेहद विपरीत परिस्थितियों में दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं।

3. पुरस्कार के लिए 10 लाख डॉलर की राशि उनके काम के लिए और एक लाख डॉलर की राशि व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दी जाती है। वर्ष 2016 में पहला औरोरा पुरस्कार दिया गया था जो एक वर्ष के भीतर ही दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी अभियान बन गया है।

4. इस बार जिन पांच लोगों को अंतिम तौर पर चयनित किया गया था उसमें डॉ. सेटाना के अलावा तालिबान इलाके में मुस्लिम लड़कियों के लिए शिक्षा अभियान चला रही जमीला अफगानी, सोमालिया में आतंकियों के चंगुल से बच्चों को छुड़ा कर उन्हें योग्य इंसान बनाने में जुटी फार्तुन अदान, युद्घग्रस्त सीरिया में अस्पताल चलाने वाले मुहम्मद दार्विश और कांगों में सैनिकों के बलात्कार से पीडि़त लड़कियों के बीच काम करने वाले डॉ.डेनिस मुक्वागे शामिल हैं।

आर्थिक

ळैज् में ऐसा करने वाला पहला सूबा

देश के अन्य राज्यों के साथ ही जम्मू-कश्मीर में भी जीएसटी लागू होगा, लेकिन एक मामले में यह सूबा बाकी प्रदेशों से आगे निकल जाएगा। जम्मू-कश्मीर पहला ऐसा राज्य हो सकता है, जो जीएसटी के दायरे में रियल एस्टेट सेक्टर को भी लाएगा। राज्य के वित्त मंत्री हसीब द्रबू ने इस बात की पुष्टि की। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में बदलाव किए हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर अपने विशेषाधिकारों के साथ ही इस नई कर व्यवस्था को लागू करेगा।

क्या है

1. द्रबू ने कहा कि राज्य में जीएसटी लागू कराने के लिए वह जरूरी विधेयक सदन में पेश करेंगे ताकि सूबे को इस कानून से जुड़े लाभ हासिल हो सकें।

2. जम्मू-कश्मीर को जीएसटी लागू करने के बाद 2,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा। इसके अलावा उसके टैक्स बेस में भी 15 पर्सेंट तक का इजाफा होगा। फिलहाल राज्य सरकार को 11,000 करोड़ रुपये की आय अप्रत्यक्ष कर के कलेक्शन से होती है।

3. जीएसटी काउंसिल ने सेंट्रल एक्साइज टैक्स, स्टेट वैट, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स समेत कई तरह के करों का विलय करने का फैसला लिया है। लेकिन राज्य सरकार के लिए आय का अहम स्रोत कहे जाने वाले आबकारी विभाग, पेट्रोलियम और रियल एस्टेट सेक्टर को इस दायरे से बाहर रखा है।

4. श्रीनगर में आयोजित होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले द्रबू ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, श्जीएसटी के दायरे में रियल एस्टेट सेक्टर को भी लाने वाले हम देश के पहले राज्य होंगे।

च्लजउ ने की पेमेंट बैंक की शुरुआत

पेटीएम ने 23 मई को पेमेंट बैंक की शुरुआत कर दी है। पेटीएम पेमेंट बैंक (पीपीबी) ने खाते में जमा राशि परि 4 फीसद का ब्याज देने का फैसला किया है। साथ ही वह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं वसूलेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक में आप सेविंग अकाउंट के साथ-साथ करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगर भविष्य की

योजनाओं की बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक की बीमा, ऋण, म्युचुअल फंड जैसी कई वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने की योजना है।

क्या है

1. पेटीएम पेमेंट बैंक एक लेनदेन बैंक है और इसलिए पीपीबी पर कोई भी ऑनलाइन लेनदेन पूरी तरह से मुफ्त होगा। यहां तक कि पेटीएम पेमेंट बैंक का यह भी दावा है कि वो इंडिया का पहला ऐसा बैंक होगा जहां पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा, साथ ही इसमें मिनिमम बैलेंस की अनिवार्य शर्त भी नहीं होगी। इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड मुफ्त में दिया जाएगा और ऑनलाइन एवं ई-मेल के माध्यम से स्टेटमेंट मंगाना भी मुफ्त होगा। हालांकि अगर आप ये स्टेटमेंट ऑफलाइन माध्यम से मंगाना चाहते हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज के साथ 50 रुपए का भुगतान करना होगा।

2. कंपनी का कहना है कि वह संचालन के पहले साल में 31 शाखाएं (ब्रांच) और 3,000 कस्टमर सर्विस प्वाइंट तक इसका विस्तार करेगी।

थ्प्च्ठ के खात्मे को को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में एफआईपीबी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसकी जगह अब एक नया तंत्र काम करेगा जिसके तहत संबंधित मंत्रालय कैबिनेट से स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया के तहत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देंगे। उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश के प्रस्तावों को गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी।

क्या करता था बोर्ड:

1. बोर्ड वैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की पड़ताल कर रहा था जिसे सरकार की स्वीकृति की जरूरत होती थी।

2. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में एफआईपीबी की समाप्ती की घोषणा की थी। यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के तहत विभिन्न मंत्रालयों के बीच काम करता था।

ळैज् पर आगे बढ़ी सरकार

श्रीनगर में 18 मई को शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 1200 से ज्यादा वस्तुओं पर कितना टैक्स लगेगा इस पर सहमति बन गई है। वहीं सर्विस टैक्स जीएसटी के अंतर्गत किस कैटेगरी में जाएगा इस पर कल फैसला संभव है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह स्पष्ट किया कि यदि 19 मई को सभी वस्तुओं और सेवाओं पर दरें का निर्धारण नहीं हो पाता है तो काउंसिल की एक बैठक और होगी।

क्या है

1. काउंसिल की ओर से लिए गए निर्णय के मुताबिक जीएसटी के लागू होने के बाद कुल 81 फीसद चीजें 18 फीसद तक के दायरे में आएंगी। वहीं, सात फीसद वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनको जीरो फीसद की स्लैब में रखा गया है।

2. 14 फीसद वस्तुएं 5 फीसद के स्लैब में, 17 फीसद वस्तुएं 12 फीसद की स्लैब में और 43 फीसद वस्तुएं 18 फीसद की स्लैब में आएंगी। वहीं, सात फीसद वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनको जीरो फीसद की स्लैब में रखा गया है। 14 फीसद वस्तुएं 5 फीसद के स्लैब में, 17 फीसद वस्तुएं 12 फीसद की स्लैब में और 43 फीसद वस्तुएं 18 फीसद की स्लैब में आएंगी।

3. जीएसटी लागू हो जाने के बाद दूध और अनाज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहीं चीनी, चाय और खाद्य तेल 5 फीसद टैक्स स्लैब के दायरे में आएंगे। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इस बात की जानकारी दी है।

ळैज् काउंसिल ने सभी 9 नियमों को दी मंजूरी

1. रजिस्ट्रेशन (त्महपेजतंजपवद): इसके अंतर्गत यह शामिल होगा कि कंपनियां और व्यापारी रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं और उसका तरीका क्या होगा।

2. रिटर्न (त्मजनतद): रिटर्न में यह बताया जाएगा कि इसके लिए कौन कौन क्लेम कर सकता है और इसे कितनी बार फाइल कराया जा सकता है, इसका फॉर्म कैसा होगा और फॉर्म का कंटेंट कैसा होगा इत्यादि।

3. रिफंड (त्मनिदक): इसमें यह बताया जाएगा कि इसके लिए किस सूरत में अनुमति दी जा सकती है। यह कितने टाइम में मिलेगा और इसकी क्या प्रक्रिया है।

4. कंपोजीशन (ब्वउचवेपजपवद): कंपोजीशन में यह बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या होगा। इसे कौन कौन लोग कर सकते हैं और कैसे।

5. ट्रांजिशन (ज्तंदेपजपवद): इसमें यह बताया जाएगा कि अगर आप किसी वस्तु एवं सेवा को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे।

6. इनवॉइस (प्दअवपबम): यह एक तरह का बिल ही होता है। इसमें यह बताया जाएगा कि यह किस तरह का होगा और कितने तरीके का।

7. पेमेंट (च्ंलउमदज): इसमें यह उल्लेख होगा कि यह कब तक किया जा सकता है, किस किस दिन किया जा सकता है और अगर किसी सूरत में टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो फिर आगे क्या प्रावधान अपनाए जाएंगे।

8. वैल्युएशन (टंसनंजपवद): इसमें यह तय किया गया है कि किसी डील के दौरान वस्तु एवं सेवा की कीमत कितनी होनी चाहिए जिस पर टैक्स लगाया जाएगा।

9. इनपुट टैक्स क्रेडिट (प्दचनज जंग ब्तमकपज): इस नियम में यह बताया गया है कि जो लोग टैक्स का भुगतान कर चुके हैं वो इसका क्रेडिट कैसे ले सकते हैं।

थ्क्प् के मामले में लगातार दूसरे साल भारत टॉप पर

भारत में वर्ष 2016 के दौरान भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) आया। इसके साथ ही ग्रीनफील्ड यानी नए प्रोजेक्टों के लिए एफडीआइ के मामले में उसने लगातार दूसरे साल अपना शीर्ष स्थान बरकरार

रखा है। बीते साल देश को 62 अरब डॉलर का एफडीआइ हासिल हुआ। इस मामले में चीन 59 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ दूसरे नंबर पर है। पिछले साल 48 अरब डॉलर के आंकड़े के साथ अमेरिका इस मामले में तीसरे नंबर पर रहा। फाइनेंशियल टाइम्स से जुड़ी एफडीआइ इंटेलीजेंस की ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

क्या है

1. रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 के दौरान भारत में 809 परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। इस दौरान पूंजीगत निवेश के हिसाब से एफडीआइ दो फीसद बढ़कर 62.3 अरब डॉलर हो गया।

2. दुनिया भर में ग्रीनफील्ड एफडीआइ छह फीसद बढ़कर 776.2 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गया। इसके चलते विश्व में पैदा होने वाली नई नौकरियां पांच फीसद बढ़कर 20 लाख से ज्यादा रहीं। जहां तक किसी सेक्टर में पूंजीगत निवेश का सवाल है, तो रियल एस्टेट इस मामले में सबसे आगे रहा।

3. केंद्र सरकार की ओर से किए गए सुधार उपायों के कारण 2016-17 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की वृद्धि दर 9.4 फीसद बढ़कर 43.48 अरब डॉलर हो गई है।

4. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि देश में एफडीआई प्रवाह में वृद्धि का कारण सरकार के एफडीआई व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने के लिए किए गए नीतिगत सुधार हैं।

5. मंत्रालय ने कहा कि देश अब विदेशी निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षक स्थान बन गया है। बयान में आगे कहा गया कि एफडीआई इक्विटी प्रवाह 2016-17 में 43.48 अरब डॉलर रहा, किसी एक वित्त वर्ष में यह सर्वाधिक है।

जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं

गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ने 19 मई को 4 टैक्स दरों पर अपनी सहमति जता दी है। सूत्रों के मुताबिक हेल्थकेयर और एजुकेशन को जीएसटी से बाहर रखा गया है और बहुत सारी सेवाओ को पहले की ही तरह छूट मिलती रहेगी। 5000 रुपए प्रति रात से ऊपर के किराए वाले होटल्स पर 28 फीसद की दर से जीएसटी लागू होगा। काउंसिल की अगली बैठक 3 जून को होगी।

किस सर्विस पर कितना टैक्सः

1. सभी सेवाओं को 5%, 12%, 18% और 28% फीसद के दायरे में ही रखा जाएगा।

2. ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाएं जैसे कि रेलवे और एयरट्रांसपोर्ट को 5 फीसद के टैक्स स्लैब में रखा जाएगा, क्योंकि इन सेक्टर से जुड़ा अहम इनपुट यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स (पेट्रोल-डीजल) को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

3. टेलिकॉम सर्विसेज पर 18 फीसद रेट तय किया गया। अभी इस पर सर्विस टैक्स 15 फीसद है। यानी जीएसटी में टेलिकॉम सर्विसेज महंगी हो जाएंगी।

4. ब्रांडेड गारमेंट पर जीएसटी की दर 18 फीसद तय की गई है।

5. बैंकिंग, इन्श्योरेंस समेत फाइनेंशियल सर्विसेज पर 18 फीसद की जीएसटी दर तय की गई है जिससे ये सर्विसेज महंगी हो जाएंगी।

6. प्रति कमरा 1 हजार रुपए से कम किराये वाले होटलों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। 1 हजार रुपए से 2500 रुपए के कमरे वाले होटलों पर 12 फीसद टैक्स रेट लागू होगा।

7. वहीं 2500 रुपए से 5 हजार रुपए के कमरे वाले होटलों पर 18 फीसद की दर से टैक्स रेट लगेगा। वहीं 5 हजार रुपए से ज्यादा किराये वाले होटलों पर 28 फीसद टैक्स रेट लगेगा।

8. फाइव स्टार होटलों पर 28 फीसदी रेट लागू होगा। नॉन एसी पर 12% और एसी के साथ लिकर लाइसेंस वालों पर 18 सर्विस टैक्स लगेगा।

9. 50 लाख या उससे कम सालाना टर्नओवर वाले छोटे रेस्टोरेंट्स की सर्विसेस पर 5% टैक्स लगेगा।

10. 28 फीसद की टैक्स रेट 5 स्टार होटल्स, रेस क्लब बैटिंग और सिनेमा के लिए लागू होगी।

11. फाइनेंशियल सर्विस के लिए 18 फीसद का सर्विस टैक्स देना होगा।

फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 लिस्ट

फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक रैंकिंग चार मापदंडों पर दी जाती है। यह मापदंड बिक्री, मुनाफा, संपत्ति और बाजार मूल्य पर आधारित है। इसमें चारों को समान महत्ता दी जाती है। लिस्ट में आरआईएल के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) है। एसबीआई इस वर्ष 244वें स्थान पर है। बीते वर्ष यह 149वें स्थान पर था। वहीं दूसरी ओर सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी 246वें स्थान पर है। यह बीते वर्ष 220वें स्थान पर थी।

क्या है

1. लिस्ट में तीन और बैंकों ने जगह बनाई है। इनमें एचएडएफसी बैंक 258वें स्थान पर, आईसीआईसीआई 31वें स्थान पर, एक्सिस बैंक 463वें स्थान पर और कोटक महिंद्रा बैंक 744वें स्थान पर है।

2. भारतीय कंपनियों में टाटा छठे स्थान पर है। वहीं वैश्विक स्तर पर यह 290वें स्थान पर है। बीते वर्ष यह 278वें स्थान पर थी।

3. वैश्विक स्तर पर चीन और अमेरिका की कंपनियां टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में शामिल है।

4. वर्ष 2017 की लिस्ट में लगातार पांचवें वर्ष चीन का इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है।

5. वहीं, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक दूसरे स्थान पर है। चीन के दो अन्य बैंक एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ चाइना टॉप 10 की लिस्ट में शुमार है।

ग्ूल बिल क्या है

केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई से लागू करना चाहती है, हालांकि महत्वपूर्ण ई-वे बिल के कार्यान्वयन में देरी से जीएसटी का समय से लागू होना थोड़ा मुश्किल जान पड़ रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये ई-वे बिल है क्या?

क्या है ई-वे बिल

1. अगर कोई वस्तु का एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के भीतर मूवमेंट होता है तो सप्लायर को ई-वे बिल जनरेट करना होगा। अहम बात यह है कि सप्लायर के लिए यह बिल उन वस्तुओं के पारगमन (ट्रांजिट) के लिए भी बनाना जरूरी होगा जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं।

2. इस बिल में सप्लायर, ट्रांसपोर्ट और ग्राही (त्मबपचपमदजे) की डिटेल दी जाती है। अगर जिस गुड्स का मूवमेंट एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक ही राज्य के भीतर हो रहा है और उसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है तो सप्लायर (आपूर्तिकर्ता) को इसकी जानकरी जीएसटीएन पोर्टल में दर्ज करानी होगी।

3. यह बिल: यह बिल बनने के बाद कितने दिनों के लिए वैलिड होता है, यह भी निर्धारित है। अगर किसी गुड्स (वस्तु) का मूवमेंट 100 किलोमीटर तक होता है तो यह बिल सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड (वैध) होता है। अगर इसका मूवमेंट 100 से 300 किलोमीटर के बीच होता है तो बिल 3 दिन, 300 से 500 किलोमीटर के लिए 5 दिन, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 10 दिन और 1000 से ज्यादा किलोमीटर के मूवमेंट पर 15 दिन के लिए मान्य होगा।

4. इस बिल के अंतर्गत विक्रेता (वस्तु के बेचने वाला) को जानकारी देनी होगी की वो किस वस्तु को बेच रहा है, वहीं खरीदने वाले व्यक्ति को जीएसटीन पोर्टल पर जानकारी देनी होगी कि उसने या तो गुड्स को खरीद लिया है या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि अगर आप कोई जवाब नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आपने वस्तु को स्वीकार कर लिया है।

5. जब आप (विक्रेता) ई-वे बिल को जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो एक यूनीक ई-वे नंबर (ईबीएन) जनरेट होगा। यह सप्लायर,ट्रांसपोर्ट और ग्राही (त्मबपचपमदजे) तीनों के लिए होगा।

विज्ञानं और तकनिकी

नए बैक्टीरिया को दिया कलाम का नाम

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नए खोजे गए बैक्टीरिया को श्सोलीबैकिलस कलामीश का नाम देकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम को अनोखी श्रद्धाजंलि दी है। अब तक यह नया सूक्ष्म जीव सोलीबैकिलस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही पाया जाता था। यह पृथ्वी पर नहीं था। नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने अंतरग्रही यात्रा पर काम करते हुए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के फिल्टरों में इस नए बैक्टीरिया को खोजा। यह बैक्टीरिया ऐसे फिल्टर पर पाया गया, जो स्पेस स्टेशन में 40 महीने तक रहा। यह फिल्टर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्वच्छता प्रणाली का हिस्सा है। इस फिल्टर का जेपीएल (जेट प्रोपल्शन लैब) में विश्लेषण किया गया। इस खोज को लैब के वरिष्ठ अनुसंधान वैज्ञानिक डॉ. कस्तूरी वेंकटस्वर्ण ने इसी साल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिस्टमेटिक एंड एवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित किया है।

क्या है

1. जीवाणुओं का घर होता स्पेस स्टेशन: पृथ्वी के कक्ष से 400 किमी ऊपर होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कई प्रकार के बैक्टीरिया व फफूंद पाए जाते हैं।

2. स्टेशन पर अंतरिक्षयात्रियों के साथ ही इनका अस्तित्व बना रहता है। डॉ. कस्तूरी वेंकटस्वर्ण मानते हैं कि हालांकि सोलीबैकिलस कलामी अब तक पृथ्वी पर नहीं पाया गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका पृथ्वी से अलग कोई जीवन है।

3. वह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह जीव किसी कार्गो के साथ स्पेस स्टेशन पहुंचा होगा और वहां की प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने को ढालने में सफल रहा होगा। नासा में डा. वेंकटस्वर्ण के पास यह अहम दायित्व है कि दूसरे ग्रहों पर जाने वाले अंतरिक्षयान बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों से मुक्त रहें।

4. कहां होते हैं बैक्टीरिया: बैक्टीरिया पृथ्वी पर मिट्टी में, अम्लीय गर्म जल धाराओं में, नाभिकीय पदार्थो में, जल में, यहां तक कि कार्बनिक पदार्थो, पौधों तथा जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं।

5. क्यों दिया कलाम का नाम: केरल के थुंबा से 21 नवंबर 1963 की शाम भारत ने पहले रॉकेट श्नाइक अपाचेश का प्रक्षेपण किया। इस रॉकेट को अमेरिका ने दिया था। इस प्रक्षेपण के साथ भारतीय रॉकेट विज्ञान का उद्भव हुआ।

6. भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक डा. विक्रम साराभाई ने 1963 में ही डा. एपीजे अब्दुल कलाम को छह महीने के विशेष प्रशिक्षण पर नासा भेजा था। कलाम के सामने रॉकेट का निर्माण हुआ था। डा. वेंकटस्वर्ण ने कहा कि वह भी डा. कलाम की तरह तमिल हैं। उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान में डा. कलाम के महती योगदान का पता है। प्राय: नये खोजे गए बैक्टीरिया को किसी महान वैज्ञानिक का नाम मिलता आया है।

भारत की सबसे मुश्किल चुनौती का निकला समाधान

चांद पर मिलने वाले हीलियम थ्री को भविष्य के ईंधन के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा अंतरिक्ष अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए चांद पर ईंधन केंद्र बनाए जाने की योजना पर काम चल रहा है। भारत ने चंद्रयान-1 के जरिए ये साबित कर दिया कि वो अब स्पेस साइंस में दुनिया के कुछ विकसित देशों के साथ कदमताल करने को तैयार है। ब्रिटेन के कल्हम साइंस सेंटर के मुताबिक हीलियम थ्री से न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकाली जा सकती है। इसके लिए बड़ी मशीन की जरुरत होगी। इसमें एक समय में एक ग्राम के सौवें हिस्से के बराबर ईंधन डाला जाता है। इस ईंधन का एक किलो उतनी उर्जा देता है जितना पेट्रोलियम का दस हजार टन देगा और इससे प्रदूषण भी बहुत ही कम होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर इतना हीलियम थ्री है कि उससे सैंकड़ों वर्षों तक पृथ्वी की ऊर्जा जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। चांद पर कई रॉकेट भेजकर हीलियम थ्री पृथ्वी पर लाया जा सकता है।

क्या है

1. चांद पर ईंधन केंद्र बनाए जाने से न केवल सुदूर अंतरिक्ष अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित करने में मदद मिलेगा, बल्कि भारत की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी। अब ये स्थापित तथ्य है कि चांद पर हीलियम थ्री का

विशाल भंडार है। जो देश आक्रामक तौर पर चंद्र अभियान को चलाएंगे वो अपनी बादशाहत आगे भी कायम रख सकेंगे। इसरो द्वारा प्रस्तावित अगले साल चंद्र-2 अभियान से भारत अमेरिका और रूस को खुलकर चुनौती देने में कामयाब होगा।

2. पृथ्वी और चांद के बीच अंतरिक्ष में मौजूद अर्थ- मून लैगरेजियन प्वाइंट(एल1) में ईंधन डिपो के रूप में एक अंतरिक्ष यान स्थापित किया जाएगा। चांद से छोटे अंतरिक्ष यानों के जरिए बर्फ को इस डिपो तक पहुंचाया जाएगा। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनियां इस चांद पर ईंधन केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रही हैं। यह केंद्र सुदूर अंतरिक्ष अभियानों के लिए ईंधन उपलब्ध कराएगा। कंपनियों ने कालटेक स्पेस चौलेंज 2017 के जरिए विश्व के 27 छात्रों के साथ इसकी संभावना तलाशी। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2020 से शुरू होगी जो 2030 में ईंधन केंद्र के रूप में सामने आएगी। इस ईंधन केंद्र में एक हजार लोगों के रहने की व्यवस्था भी होगी।

3. सुदूर अंतरिक्ष अभियानों के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत होती है। लेकिन इतना ईंधन ले जाना संभव नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए अंतरिक्ष यान को 11 किमी प्रति सेकेंड की रफ्तार से वजनी ईंधन के साथ उड़ान भरते हैं। इस दौरान अधिक ऊर्जा के लिए अधिक ईंधन की खपत होती है। ईंधन की बड़ी मात्रा इतने सफर में ही समाप्त हो जाती है। इस वजह से सुदूर अंतरिक्ष अभियान संभव नहीं हो पाता है।

4. पृथ्वी से अंतरिक्ष यान को एक खाली ईंधन टैंक के साथ निचली कक्षा में लांच किया जाएगा। वहां से उसे एक सौर ऊर्जा चालित यान की की सहायता से एल1 तक ले जाकर उससे जोड़कर उसमें ईंधन भरा जाएगा।

5. डिपो में सौर ऊर्जा की मदद से बर्फ पिघलाई जाएगी। फिर विद्युत अपघटन के जरिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त किए जाएंगे। अत्याधुनिक रॉकेट में ईंधन के रूप में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है।

इस ग्रह पर होता है सिर्फ 19 दिन का एक साल

अगर उम्र को साल में नापा जाए तो एक ग्रह ऐसा भी है जहां आपकी उम्र 20 गुना हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रह पर साल में सिर्फ 19 दिन ही होते हैं। इस ग्रह के सूरज का नाम ट्रेपिस्ट-1 है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस ग्रह को खोजा था।

क्या है

1. वैज्ञानिकों ने केपलर दूरबीन से इसके ग्रह की परिक्रमा अवधि का पता लगाया है। धरती से करीब 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित ट्रेपिस्ट-1 का द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में आठ गुना कम है। इसकी उम्र तीन से आठ अरब साल के बीच होने का अनुमान है।

2. इसी कारण इसकी चमक और ऊष्मा में भी कमी है। इस तारे के चारों ओर धरती के आकार के सात ग्रह परिक्रमा करते हैं। इनमें सबसे बाहरी छोर पर स्थित ग्रह धरती के हिसाब से मात्र 19 दिन में ही इसकी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है।

वॉनाक्राइ अनलॉक करने का तरीका

फ्रांस के रिसर्चर्स ने 19 मई को कहा कि उन्होंने वॉनाक्राइ रैन्समवेयर से सिस्टम की फाइलों को बचाने का एक तरीका ढूंढ निकाला है। इसके जरिए उन कंप्यूटरों और उनकी फाइलों को बचाया जा सकता है जो वॉनाक्राइ का शिकार

हुए हैं और जिन्हें एक हफ्ते में फिरौती न दिए जाने की सूरत में लॉक कर दिए जाने की धमकी दी गई है। इस टूल को रिसरचर्स ने वॉनाकीवी नाम दिया है।

क्या है

1. बता दें कि वॉनाक्राइ ने 12 मई को दुनियाभर में कहर बरपाना शुरू किया था और यह अब तक 150 देशों के 3 लाख कंप्यूटरों को अपना निशाना बना चुका है। वॉनाक्राइ अपने शिकार को धमकी देता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर 300 से 600 मिलियन डॉलर फिरौती के तौर पर नहीं दिए गए तो सिस्टम को हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाएगा।

2. दुनियाभर में फैले सिक्यॉरिटी रिसर्चर्स की एक टीम इस काम के लिए साथ आई और उन्होंने मिलकर उन फाइलों को खोलने का तरीका ढूढ लिया जो इस ग्लोबल साइबर अटैक का शिकार हुई हैं। कई अन्य सिक्यॉरिटी रिसर्चर्स ने भी इस टूल के काम करने की पुष्टि की है।

3. हालांकि रिसर्चर्स ने यह भी बताया है कि उनका तरीका कुछ खास परिस्थितियों में ही काम करेगा। जो कंप्यूटर साइबर अटैक का शिकार हुआ है, अगर उसे रीबूट नहीं किया गया हो तभी यह टूल उस पर काम करेगा। इसके अलावा वॉनाक्राइ ने अभी तक जिन कंप्यूटरों की फाइलों को पर्मानेंटली बंद नहीं किया है, यह टूल उन्हीं पर असर करेगा।

4. रिसर्चर्स की टीम ने दिन-रात जागकर यह टूल बनाया है क्योंकि उन्हें पता था कि वक्त ज्यादा नहीं है। उन्हें अहसास था कि वक्त बीतने के साथ फाइलों को बचाना मुश्किल होता जाएगा। फिरौती दिए बगैर अपनी फाइलों को फिर हासिल करने के इस फ्री टूल नाम श्वॉनाकीवीश रखा गया है।

5. वॉनाकीवी विडोज 7 और विंडोज के पुराने वर्जन ग्च और 2003 पर काम कर रहा है। साथ ही विडोज 2008 और विस्टा पर भी।

6. टीम के एक सदस्य ने कहा, श्यह तरीका ग्च से लेकर ॅपद7 तक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना चाहिए।श उन्होंने बताया कि अभी तक बैंकिंग और ऊर्जा संस्थानों के अलावा कई देशों की खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर उनसे संपर्क किया है। इनमें यूरोपीय देशों के अलावा भारत भी शामिल है।

दुनिया की पहली सुपर दूरबीन से खुलेगा ब्रह्मांड का राज

दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल और इंफ्रारेड दूरबीन चिली में बनाया जा रहा है जिससे वैज्ञानिकों को ब्रहमांड की आतंरिक गतिविधियों को समझने में मदद मिलेगी। यूरोपियन सदर्न ऑब्जवेर्टरी (ईएसओ) द्वारा बनाए जा रहे इस अत्यधिक विशाल दूरबीन (ईएलटी) में मुख्य दर्पण का व्यास 39 मीटर का है। दूरदर्शी आमतौर पर उस प्रकाशीय तंत्र को कहते हैं जिससे देखने पर दूर की वस्तुएं बड़े आकार की और स्पष्ट दिखाई देती हैं।

क्या है

1. इस दूरबीन की खासियत यह है कि इसे ऑप्टिकल सिस्टम का प्रदर्शन सुधारने के लिए इस्तेमाल करने वाली प्रौद्योगिकी एडेप्टिव ऑप्टिकल से बनाया जा रहा है और इसमें वायुमंडलीय विक्षोभ को सही करने की क्षमता है जो दूरबीन इंजीनियरिंग को दूसरे स्तर पर ले जाती है।

2. इस विशाल दूरबीन का निर्माण 2024 तक कर लिया जाएगा। इसे चिली में 3046 मीटर ऊंचे पर्वत सेरो आर्मजोन की चोटी पर बनाया जाएगा।

3. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस परियोजना में अहम भूमिका निभा रहे हैं और वे इसके स्पेक्ट्रोग्राफ के डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं।

4. ईएसओ के महानिदेशक टिम डीई जीउव ने कहा कि ईएलटी से नहीं खोजें होंगी जिनकी आज कल्पना नहीं की जा सकती और निश्चित रूप से यह दुनिया में कई लोगों को विज्ञान, तकनीक और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगा।

श्ऑपरेशन क्लीन मनीश वेबसाइट

कालेधन और टैक्सचोरी के खिलाफ केंद्र सरकार ने नया कदम उठाया है। इसके तहत सरकार अब इनकम टैक्स विभाग के छापों की रिपोर्ट्स एक वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगी। साथ ही डिफॉल्टर्स को हाई रिस्क से वेरी लो रिस्क कैटिगरी में डिवाइड करके इस वेबसाइट पर उनकी लिस्ट भी डाली जाएगी। वेबसाइट लॉन्च के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि नोटबंदी के बाद 91 लाख नये करदाताओं की पहचान की गई। इस वेबसाइट का नाम है- ऑपरेशन क्लीन मनी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह वेबसाइट 16 मई को लॉन्च की।

क्या है

1. वित्त मंत्री ने बताया कि विमुद्रीकरण से डिजिटाइजेशन को काफी बढ़ावा मिला। साथ ही कैश ट्रांजैक्शन के खतरों को देखते हुए टैक्स पेयर्स की संख्या और टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

2. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद 91 लाख नये करदाता सामने आये। अभी उन्हें टैक्स रिटर्न में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। नोटबंदी के बाद व्यक्तिगत आयकर संग्रह में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

3. डिफॉल्टर्स के खिलाफ हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क और वेरी लो रिस्क जैसी कैटिगरीज के तहत अलग-अलग ऐक्शन लिये जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक हाई रिस्क कैटिगरी में आने वाले लोगों और समूहों को तलाशी, जब्ती और सीधी जांच जैसी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।

4. मीडियम रिस्क कैटिगरी को ेडै या ईमेल के जरिये सूचना भेजी जाएगी ताकि वे सुधार के उपाय कर सकें और लो रिस्क या वेरी लो रिस्क कैटिगिरी के डिफॉल्टर्स पर नजर रखी जाएगी। स्कैनिंग के तहत आने वाले व्यक्तियों या समूहों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी।

5. नोटबंदी के बाद आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग में 22 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। नोटबंदी के बाद 17.92 लाख ऐसे लोगों का पता लगाया गया है जिनके पास जमा कराई गई नकदी का हिसाब किताब नहीं है। इसके अलावा कर विभाग ने एक लाख संदिग्ध कर चोरी के मामलों का भी पता लगाया है।

ईपीएफओ के ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय ने बेंगलुरू में ईपीएफओ के नागरिक चार्टर 2017 और ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। नागरिक चार्टर 2017 का उद्देश्य ईपीएफओ की ओर से होने वाले कामकाज में पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इससे सेवा प्रदान करने से जुड़ी प्रणाली एवं शिकायत निवारण व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी जिससे इसके समस्त हितधारकों को वस्तुओं एवं सेवाओं को समयबद्ध ढंग से मुहैया कराया जा सकेगा। इसके तहत निर्धारित समय सीमा भी कम हो जायेगी, जो वर्तमान में 30 दिन है। दावा निपटान के मामले में समय सीमा 10 दिन और शिकायत निवारण प्रबंधन के मामले में समय सीमा 15 दिन है। सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज उपलब्ध कराने के विजन के साथ नागरिक या सिटीजन चार्टर को लांच किया गया है। इसका एक अन्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त सहायता के साथ सभी हितधारकों के फायदे के लिए नीतियों को क्रियान्वित करना है।

क्या है

1. ईपीएफओ की ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ डिजिटल इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

2. इस परियोजना का उद्देश्य एक पारदर्शी एवं इलेक्ट्रॉनिक मामला प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करना है जो सभी हितधारकों यथा नियोक्ताओं, कर्मचारियों, याचिकाकर्ताओं और सीबीटी की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। यह पेपरलेस कोर्ट प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम 1952 और ईपीएफएटी की अदालती प्रक्रिया डिजिटल तरीके से पूरी होगी।

3. ट्रिब्यूनल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं के पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर उनके मामलों की ताजा स्थिति के बारे में स्वचालित संदेश भेजे जायेंगे। इसी तरह हितधारक भी विभिन्न मामलों पर ऑनलाइन नजर रख सकेंगे।

4. अब से संबंधित पक्ष अपने सभी कागजात/साक्ष्य/दस्तावेजों को ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे और ताजा स्थिति के साथ-साथ सभी विवरण से ऑनलाइन अवगत हुआ जा सकेगा।

दुनिया में पहली बार पतंग से बनेगी बिजली

ब्रिटेन में अब पतंग से बिजली बनेगी। इसके लिए वैज्ञानिक विशाल पतंगों की मदद से चलने वाला बिजली संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। इस बिजली से 5,500 घरों को रोशन किया जा सकेगा। यहां 20 पतंगों को उड़ाकर बिजली पैदा की जाएगी। पतंगों की ऊंचाई 300 मीटर से भी ज्यादा होगी।

ऐसे बनेगी बिजली

1. बीस पतंगों को दो--दो के जोड़ों में तीन सौ मीटर की ऊंचाई पर 160 किमी प्रति घंटा से ज्यादा की गति से गोलाकार (एक सर्कल में) उड़ाया जाएगा।

2. ये पतंगें एक जेनरेटर से जुड़े ड्रम पर लिपटी रस्सी से बंधी होंगी। पतंगों के उड़ने से ड्रम चलेगा। इससे जेनरेटर जुड़ा होगा और बिजली का उत्पादन होगा। जैसे ही पतंग ड्रम के ऊपर पहुंच जाएगी दूसरी पतंग से चलने वाला ड्रम पहली पतंग को वापस खींच लेगा। इससे फिर बिजली बनेगी और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। दो-दो पतंगें इस तरह चलेगी कि प्रक्रिया निरंतर चलेगी।

3. स्कॉटलैंड की कंपनी काइट पावर सिस्टम्स (केपीएस) ने इसकी मदद से 40 किलोवाट की उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र का सफल परीक्षण किया है। वर्ष 2020 तक कंपनी की योजना 500 किलोवाट का संयंत्र स्थापित करने की है।

4. केपीएस के बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर डेविड एंसवर्थ ने कहा कि पतंग पवन चक्कियों की तुलना में बेहद सस्ती होती है। साथ ही, पतंगों को 300 मीटर से भी ऊपर उड़ाया जा सकता है। यह ऊंचाई पवन चक्कियों की तुलना में दोगुनी है।

5. 2020 तक सैकड़ों पवन चक्कियां परिचालन के योग्य नहीं रह जाएंगीं। इन पतंगों को ऐसी पवन चक्कियों के ऊपर लगाकर पतंगों की ऊंचाई को और बढ़ाया जा सकता है।

इस तकनीक से सुरक्षित उतरेंगे ड्रोन

नासा के वैज्ञानिकों ने मानवरहित ड्रोन के बढ़ते चलन और इससे होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से किसी गड़बड़ी की सूरत में ड्रोन की आपात लैंडिंग कराने में मदद मिलेगी।

क्या है

1. शोधकर्ताओं के अनुसार, आसमान में बढ़ते ड्रोन से जान-माल को खतरा बढ़ गया है। उनके तकनीकी गड़बड़ी के चलते इनके गिरने की आशंका रहती है।

2. इसी को ध्यान में रखकर नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर की तकनीकी विशेषज्ञ पेट्रिसिया ग्लैब और सहयोगियों ने ड्रोन के लिए क्रैश-लैंडिंग साफ्टवेयर विकसित किया है।

3. ग्लैब ने बताया कि ड्रोन की आठ उड़ानों के दौरान इस तकनीक का परीक्षण किया गया। ड्रोन ने कार और लोगों पर गिरने की जगह सुरक्षित लैंडिंग के लिए उन जगहों का चयन किया जहां जलभराव था।

4. फॉर्च्यून डॉटकॉम की खबर के अनुसार, यह साफ्टवेयर ड्रोन के मोटर और बैटरी आदि पर नजर रखता है। ड्रोन में कोई खराबी आने पर साफ्टवेयर उसकी पहचान करके उसे क्रैश-लैंडिंग मोड में कर देता है।

5. इसके बाद यह खुद आसपास के सुरक्षित स्थान की तलाश करके ड्रोन को उस ओर ले जा सकता है। इस तकनीक से ड्रोन जमीन पर किसी वस्तु से टकराने से भी बच सकता है।

विविध

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि 61 साल के अनिल दवे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से काफी समय से जुड़े रहे। पिछले साल ही उन्हें पर्यावरण मंत्री का पदभार दिया गया था। एक साल भी अभी उन्हें इस पद को संभाले नहीं हुआ है। अनिल माधव दवे ने अपना जीवन पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया था। नर्मदा बचाओ अभियान से भी वह जुड़े हुए थे। शायद यही वजह थी कि उन्हें पिछले साल 5 जुलाई 2016 को केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री का पद दिया गया था।

क्या है

1. संघ के प्रचारक के रूप में सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाले अनिल माधव दवे एक आम भाजपा कार्यकर्ता से राजनीतिक सफर शुरू कर केंद्रीय मंत्री पद तक पहुंचे थे।अनिल माधव दवे मध्यप्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य तथा भारत सरकार में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री थे।

2. उनका जन्म 6 जुलाई 1956 में उज्जैन (भदनगर) में हुआ। इंदौरा के गुजराती कॉलेज से एम कॉम करने वाले अनिल शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। वह सालों से नर्मदा नदी बचाओ अभियान में काम कर रहे थे।

3. अनिल माधव दवे राज्यसभा में साल 2009 मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जल संसाधन समिति और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार समिति में भी थे। ग्लोबल वार्मिंग पर संसदीय समिति के भी वह सदस्य रह चुके थे।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष

श्री सैयद गय्यूर-उल-हसन रिजवी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण के बाद श्री रिजवी ने कहा कि आयोग अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए कार्य करेगा।

क्या है

1. श्री सैयद गय्यूर-उल-हसन रिजवी कला से स्नातक हैं और उनके पास यांत्रिकी में भी डिप्लोमा है।

2. उन्होंने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।

3. श्री रिजवी बढ़-चढ़कर समाज सेवा में भाग लेते रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बुनकर समुदाय तथा बीड़ी श्रमिकों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं में सुधार तथा काम करने की परिस्थितियों में सुधार के लिए कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य किया है।

संसद रत्न पुरस्कार 2017

इस वर्ष 9 सांसद श्संसद रत्न पुरस्कार 2017श से सम्मानित होंगे। इसमें लोकसभा के छह और राज्यसभा के तीन सांसद हैं। प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन के अध्यक्ष के. श्रीनिवासन ने बताया, केरल के राज्यपाल और सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी.सतशिवम सांसदों को यह पुरस्कार देंगे। ये पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन और ईमैगजीन प्रीसेंस द्वारा दिए जाते हैं। यह पुरस्कारों का आठवां संस्करण है जो सांसदों को सम्मानित करने के लिए सिविल सोसाइटी द्वारा दिया जाने वाला यह एकमात्र पुरस्कार है।

क्या है

1. पुरस्कारों के लिए चयनित सांसदों को उनके द्वारा चर्चाओं में शामिल होने की संख्या, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या, विधेयकों को पेश करने की संख्या, संसद में उनकी उपस्थिति और सासंद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड के इस्तेमाल पर तय किया जाता है।

2. पुरस्कारों के लिए जूरी समिति ने विभिन्न श्रेणियों में श्रीरंग अप्पा बार्ने (शिवसेना, मावल, महाराष्ट्र), राजीव शंकरराव सातव (कांग्रेस, हिंगोली, महाराष्ट्र) और धनंजय भीमराव महाडिक (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र)को नामित किया है।

3. जूरी समिति ने चर्चाओं की गुणवत्ता और अन्य संसदीय गतिविधियों में सांसदों की उत्कृष्टता के लिए विशेषष पुरस्कारों के लिए भर्तृहरि महताब (बीजू जनता दल, कटक, ओडिशा) और एनके. प्रेमचंद्रन (रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी कोल्लम, केरल) को नामित किया है। श्रीनिवासन ने कहा कि हीना विजयकुमार गावित (भाजपानंदुरबार, महाराष्ट्र) को महिला सांसद श्रेणी के तहत नामित किया गया है।

4. पिछले साल से राज्यसभा के उत्कृष्ट सदस्यों को भी सम्मानित किया जा रहा है जो पिछले साल अपने छह साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए थे।

5. संजय राउत (शिवसेना, महाराष्ट्र), के एन बालागोपाल (माकपा, केरल) और डॉ. टीएनसीमा (माकपा, केरल) वे राज्यसभा सांसद हैं जो 2016 में अपने छह साल का कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हो गए हैं और इन्हें उत्कृष्ट कामकाज के लिए सम्मानित किया जाएगा।

6. आनंदराव अडसुल (पांच बार के सांसद) की अध्यक्षता में ज्यूरी समिति में हंसराज अहीर (गृहराज्य मंत्री और चौथी बार सांसद) और अर्जुनराम मेघवाल (वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्यमंत्री) शामिल हैं। ज्यूरी सदस्यों को संसद महारत्न अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।

फोर्ब्स की गेम चेंजर्स सूची

रिलायंस इंडस्ट्रिज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स की ग्लोबल गेम चेंजर्स की सूची में जगह बनाई है। इस सूची में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने अपने उद्योग में बदलाव किया और लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया। फोर्ब्स की सालाना जारी होने वाली सूची में 25 लोगों को शामिल किया गया है। फोर्ब्स की दूसरी वार्षिक ग्लोबल चेंजर्स की सूची में उन निडर बिजनेस लीडर्स को शामिल किया गया है जो अपनी मौजूदा स्थिति से असंतुष्ट थे। इन लोगों ने अपने उद्योग में बड़ा बदलाव किया और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दीं।

क्या है

1. मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में उनकी मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो के कारण शामिल किया गया है। उन्होंने देश की आम जनता तक इंटरनेट की पहुंच बनाई।

2. फोर्ब्स के मुताबिक ऑयल और गैस के बडे़ कारोबारी अंबानी ने टेलीकॉम बाजार में उतरकर सस्ते दामों पर तेज इंटरनेट सेवा देने की पहल की है। उन्होंने सिर्फ छह महीनों में ही दस करोड़ ग्राहक बना लिये।

3. फोर्ब्स ने कहा कि सूची में 25 गेम चेंजर्स को वर्णानुक्रम में रखा है। तमाम उद्योगपति रिकॉर्ड मुनाफा और दूसरे कारोबारी सफलताओं के मामले में सुर्खियों में आते हैं। लेकिन फोर्ब्स ने बदलाव लाने वाले ऐसे लोगों को शामिल किया है जिन्होंने अपनी पहल से सिर्फ अपने शेयरधारकों और कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि दूसरे लाखों-करोड़ों लोगों के लिए बदलाव का रास्ता प्रशस्त किया।

सूची में ये भी शामिल

1. फोर्ब्स की इस सूची में होम एप्लाएंसेज कंपनी डायसन के संस्थापक जेम्स डायसन, अमेरिकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन ब्लैकरॉक के सह संस्थापक लेरी फिंक, सऊदी अरब के डिप्टी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सोशल मीडिया कंपनी स्नैप के सह संस्थापक चेंग वाई और अफ्रीका के रिटेल सेक्टर के कारोबारी क्रिस्टो वीज को स्थान मिला है।

2. रिलायंस जियो की सफलता के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने श्लाइट रीडिंगश के शहॉल ऑफ फेम 2017श में प्रवेश किया है। लाइट रीडिंग न्यूयॉर्क की ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की इन्फोर्मेशन कंपनी है।

3. लाइट रीडिंग के इंटरनेशनल ग्रुप एडिटर रे ली मैस्ट्री ने इस आशय की घोषणा करते हुए कहा कि इसमें उन लोगों को चुना जाता है जो ग्लोबल कम्युनिकेशन में योगदान करते हैं। लाइट रीडिंग के अनुसार मुकेश अंबानी को यह सम्मान इस वजह से नहीं दिया गया है कि वे सबसे धनी भारतीय है। बेशक वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। लेकिन उन्हें दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेशन मार्केट में बड़ा बदलाव लाने के कारण सम्मान दिया गया है।

4. मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अप्रैल में बीएसई पर सबसे मूल्यवान स्टॉक्स बन गए हैं। कंपनी को टीसीएस को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी की इस साल अप्रैल महीने तक कुल पूंजी में 700 करोड़ डॉलर तक की तेजी देखने को मिली है।

5. पूंजी में यह तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में बढ़त और टेलिकॉम कंपनी रियालंस जियो को मिली अच्छी प्रतिक्रिया के चलते हुई है। जियो के सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या वित्त वर्ष 2017 के अंत तक 10.9 करोड़ पर पहुंच गई है।

क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया की सर्वे

आनंद विहार जम्मू तवी, लखनऊ तथा गोरखपुर स्टेशन का शुमार देश के सबसे साफ-सुथरे स्टेशनों में किया गया है। विशाखापत्तनम और ब्यास देश के सर्वाधिक स्वच्छ स्टेशन हैं। जबकि दरभंगा और जोगबनी का शुमार सबसे गंदे स्टेशनों में किया गया है। आइआरसीटीसी द्वारा रेलवे स्टेशनों में साफ-सफाई की स्थिति के आधार पर कराए गए तीसरे सर्वे में, जिसे रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने जारी किया, यह तथ्य उजागर हुआ है। इसमें ए1 श्रेणी के 75 तथा ए श्रेणी 332 स्टेशनों समेत कुल 407 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया। इसी तरह की सर्वे अब ट्रेनों के बाबत भी किया जा रहा है। परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे।

क्या है

1. सर्वे की खास बात देश की राजधानी दिल्ली के सबसे प्रमुख नई दिल्ली स्टेशन का ए1 स्टेशनों में 39वां स्थान पाना है। इससे उत्तर रेलवे की बड़ी फजीहत हुई है।

2. नई दिल्ली से बेहतर स्थिति तो हजरत निजामुद्दीन व पुरानी दिल्ली स्टेशन की है जो क्रमश: 23वें एवं 24वें स्थान पर रहे हैं। आनंद विहार को भी पांचवां स्थान मिल गया है।

3. जबकि तीसरा स्थान पाकर जम्मू तवी ने उत्तर रेलवे की इज्जत बचा ली है। लखनऊ को छठा, गोरखपुर को 12वां स्थान मिलने से पूर्वोत्तर रेलवे को राहत मिली है। परंतु तमाम प्रयासों के बावजूद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 14वां स्थान मिलने से उत्तर रेलवे की किरकिरी हुई है।

4. पटना 28वें, हरिद्वार 30वें और आगरा 35 स्थान पर हैं। ए1 श्रेणी के स्टेशनों में दरभंगा, जबकि ए श्रेणी के स्टेशनों में जोगबनी का नाम लिस्ट में सबसे आखिरी है। ए श्रेणी के स्टेशनों में हिमाचल प्रदेश का ब्यास स्टेशन पूर्व की तरह पहले नंबर पर काबिज है।

5. इस सर्वे को आइआरसीटीसी के लिए क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया ने किया। जिसने रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता को मापने के लिए टायलेट, पेयजल बूथ, खानपान स्टॉल, फूट ओवरब्रिज, पटरियों तथा कूडे़दानों के अलावा पार्किंग एरिया, प्रवेश द्वार तथा प्रतीक्षालय की स्वच्छता पर खास तौर पर गौर किया। सर्वे में स्वच्छता के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के अलावा निरीक्षण के दौरान पाई गई स्थिति तथा यात्रियों की राय-सभी को अलग-अलग एक तिहाई वेटेज दी गई।

बंगाल की खाड़ी में आया श्मोराश चक्रवात

बंगाल की खाड़ी में आया श्मोराश चक्रवात अगले 12 घंटों में भयावह रूप धारण कर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटों में पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई है। इस दौरान मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है।

क्या है

1. बंगाल की खाड़ी में आए मोरा तूफान की वजह से दक्षिण-पश्चिम मानसून के जल्द दस्तक देने की उम्मीद है। लेकिन इससे काफी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।

2. मोरा एक चक्रवाती तूफान है। इस समय इसकी गति 125 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिसकी रफ्तार बढ़ भी सकती है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से मानसून केरल से पहले पूर्वोत्तर भारत में दस्तक देगा।

3. स्काइमेट वेदर के मुताबिक, मोरा तेजी से नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा है और 30 मई को चटगांव के पास बांग्लादेश तट को पार कर जाएगा। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश हो सकती है।

4. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 30 मई को दक्षिण असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम में भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल और नागालैंड में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

5. इसके साथ ही यह आशंका जताई जा रही है कि अगले 48 घंटों में दक्षिण असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में 45 से 65 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। मोरा चक्रवात की वजह से 29 और 30 मई को मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ तटीय क्षेत्र के लोगों को सर्तक रहने की सलाह दी गई है।

गूगल इंडिया की रिपोर्ट

भारत में गोवा सबसे ज्यादा दर्शनीय पर्यटक स्थल है। गूगल इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा बार गोवा के बारे में सवाल पूछे गए। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो भारत में रहने वाले लोगों को अमेरिका ज्यादा भाता है। गूगल इंडिया रिपोर्ट ने मौजूदा साल में फरवरी से अप्रैल माह के दौरान की गई सर्च के आंकड़े जारी किए हैं। ये बताते हैं कि अंडमान व निकोबार की लोकप्रियता में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। भारतीयों ने इस द्वीप समूह के बारे में जानकारी एकत्र करने में काफी रुचि दिखाई है, जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता में 39.8 फीसद की बढ़ोतरी पहले की अपेक्षा दिखी है।

क्या है

1. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अमेरिका भारतीयों को सबसे ज्यादा लुभा रहा है लेकिन नेपाल, इंडोनेशिया व भूटान को लेकर भी लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है। यही वजह है कि नेपाल की लोकप्रियता में 64.8, इंडोनेशिया की 42.1 व भूटान में 40.8 फीसद की बढ़ोतरी देखी जा रही है।

2. रिपोर्ट बताती है कि महानगरों की अपेक्षा छोटे शहरों के निवासी यात्रा संबंधी जानकारी को लेकर ज्यादा सवाल कर रहे हैं। इनकी तादाद 70 फीसद है जबकि दिल्ली व मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाले लोगों में 40.8 फीसद लोग ही इस सिलसिले में सवाल जवाब करते देखे गए हैं। 96 फीसद लोग अपने मोबाइल के जरिये इस तरह के सवाल-जवाब करते हैं।

भारत के टाप तीन पर्यटक स्थल

1. गोवा
2. अंडमान व निकोबार
3. मनाली

अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल

1. अमेरिका
2. यूएई
3. थाईलैंड

भारतवंशी ने जीती नेशनल ज्योग्राफिक बी प्रतियोगिता

पिछले साल प्रणाय को इस प्रतियोगिता में से खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन इस बार वह ठान कर आए थे कि जीत कर जाना है। 14 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी छात्र प्रणाय वरदा ने प्रतियोगिता में समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखते हुए प्रतिष्ठित + 50,000 के इनाम वाली नेशनल ज्योग्राफिक बी प्रतियोगिता जीत ली है। वरादा ने प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीतने के तुरंत बाद कहा, श्मुझे पूरा यकीन था कि मैं इस चुनौती को जीत सकता हूं।श बता दें कि पिछले एक दशक से इस प्रतियोगिता में भारतीय-अमेरिकियों का वर्चस्व रहा है।

क्या है

1. टेक्सास के एक स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्र वरदा ने कहा, श्इतने लंबे समय से ऐसा करने और इसे जीतने के बाद, अब संतुष्टि की भावना महसूस हो रही है।
2. बता दें कि वरदा ने पिछले साल भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। लेकिन वह दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कुनलुन पहाड़ की पहचान करके यह प्रतियोगित जीत ली। नेशनल ज्योग्राफिक बी प्रतियोगिता जीतने वाले छात्र को छात्रवृत्ति में 50,000 डॉलर और अन्य पुरस्कार मिलते हैं।
3. इस साल प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर भी भारतीय-अमेरिक छात्र वेदा भट्टाराम रहे, जो न्यूजर्सी में रहते हैं।
4. वहीं दूसरे स्थान पर थॉमस राइट रहे, जिन्हें 25000 डालर की छात्रवृति इनाम स्वरूप मिली है। इस साल फाइनल 10 प्रतियोगियों में से 6 भारतीय-अमेरिकी छात्र थे।

एंटी टेररिज्म डे

21 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस दिन को आतंकवाद रोधी दिवस (एंटी टेररिज्म डे) के रूप में भी मनाया जाता है। 21 मई 1991 को लिट्टे आतंकवादियों ने राजीव गांधी की हत्या की थी। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य देश में एकता, शांति, भाईचारा और समन्वय को बनाए रखना है। भारत लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित है। पड़ोसी देशों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय और भारत की जमीन पर ही पनपे आतंकी गुटों ने देश में खूब खून बहाया है। इस अवसर पर एक नजर हाल के वर्षों में भारत में हुई बड़ी आतंकी घटनाओं पर...

26/11 मुंबई हमला

1. समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आत्मघाती आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2011 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला किया।
2. आतंकियों ने कामा अस्पताल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबराय ट्राइडेंट होटल, ताज महल होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और मेट्रो सिनेमा में कत्ल-ए-आम मचाया। आतंकी घटना में 166 लोग मारे गए, जबकि 293 देशी-विदेशी नागरिक घायल हुए।

3. पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के भेजे 9 आतंकियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया, जबकि एक आतंकी अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब को लंबी चली सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने और राष्ट्रपति से भी माफी नहीं मिलने पर फांसी दी गई।

1993 मुंबई धमाके

1. 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार धमाके भारत में सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक थे।

2. इन धमाकों से मुंबई ही नहीं पूरा देश हिल गया था। यह धमाके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और इसकी डी-कंपनी ने कराए। यह धमाके माहिम में मछुआरों की कॉलोनी, जावेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, सेंचुरी बाजार, कथा बाजार, सी रॉक होटल, सहार एयरपोर्ट, एयर इंडिया बिल्डिंग, जूहू सेंटूर होटल, वर्ली, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग और पासपोर्ट दफ्तर में हुए।

3. कहा जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इसमें अहम भूमिका निभायी और कई पाकिस्तानी व भारतीय तस्करों ने इसके लिए रुपये उपलब्ध कराए थे।

4. इन धमाकों में 257 लोग काल के गाल में समा गए, जबकि 713 लोगों को चोटें आईं।

2002 अक्षरधाम मंदिर हमला, अहमदाबाद

1. गुजरात के सबसे बड़े शहरों में से एक अहमदाबाद स्थित अक्षरधाम मंदिर में 24 सितंबर 2002 को आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया।

2. लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकी मुर्तजा हाफिज यासिन व अशरफ अली मोहम्मद फारूक दोपहर करीब तीन बजे स्वचालित हथियारों और हैंड ग्रेनेड के साथ मंदिर परिसर में घुसे। यहां उन्होंने निर्दोष महिलाओं, बच्चों और पुरुषों पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया।

3. रात तक एनएसजी कमांडो ने इन दोनों आतंकियों को मार गिराया। इस आतंकी कृत्य में 31 लोगों की मौत हुई, जबकि 80 घायल हो गए।

2005 दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट

1. दिवाली से सिर्फ दो दिन पहले 29 अक्टूबर 2005 को धनतेरस के दिन आतंकियों ने सिलसिलेवार धमाके कर राजधानी दिल्ली को दहला दिया।

2. पाकिस्तानी आतंकी संगठन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फ्रंट ने दिल्ली में तीन धमाके किए।

3. इनमें से दो धमाके तो सरोजनी नगर और पहाड़गंज के मुख्य बाजारों में हुए, जबकि तीसरा धमाका गोविंदपुरी इलाके में एक बस में हुआ।

4. इन धमाकों में 63 लोगों की असामयिक मौत हुई, जबकि 210 लोगों को चोटें आईं।

2006 मुंबई ट्रेन धमाके

1. मुंबई की लाइफलाइन कही जानी वाली लोकल ट्रेन में 11 जुलाई 2006 को सिलसिलेवार ढंग से 7 बम धमाके हुए।

2. सभी बम प्रेसर कुकर के अंदर फर्स्ट क्लास कोच में रखे गए थे। सभी बम उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के पास फटे, जिनमें माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, भयंदर और बोरीवली स्टेशन शामिल थे। इन धमाकों में 210 लोग मारे गए, जबकि 715 यात्रियों को चोटें आई। कई दौर की जांच के बाद पाया गया कि इन धमाकों के लिए इंडियन मुजाहिद्दीन नामक आतंकी संगठन जिम्मेदार था।

2008 जयपुर धमाके

1. गुलाबी शहर नाम से मशहूर जयपुर को आतंकवादियों ने 13 मई 2008 को खून से लाल करने की साजिश रची।

2. सिर्फ 15 मिनट के अंदर शहर में 9 सिलसिलेवार बम धामके हुए, जबकि सुरक्षा एजेंसियों को 10 बम को डिफ्यूज करने में सफलता मिली।

3. बम 6 अलग-अलग जगहों- बड़ी चौपार, मनक चौक पुलिस स्टेशन इलाका, जौहरी बाजार, त्रिपोली बाजार, छोटी चौपार और कोतवाली इलाके में रखे गए थे। इन धमाकों में 63 लोगों की जान गई, जबकि 210 लोग घायल हो गए।

4. जयपुर में इससे पहले कभी कोई आतंकी हमला नहीं हुआ था, 9 में से एक धमाका तो शहर के मशहूर हवा महल महल के पास हुआ।

2008 असम धमाके

1. असम में 30 अक्टूबर 2008 को अलग-अलग इलाकों में 18 बम धमाके हुए। राजधानी गुवाहाटी के अलावा बारपेटा रोड, बोंगाईगांव और कोकराझार में यह धमाके हुए। ज्यादातर बम धमाके मुख्य बाजारों के आसपास ऐसे वक्त पर हुए, जब उनमें सबसे ज्यादा भीड़ रहती है।

2. इन धमाकों में 81 लोगों की मौत हुई, जबकि 470 लोग घायल हुए थे। इन धमाकों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन इनमें एनडीएफबी का हाथ होने की सबूत मिले थे।

2001 संसद भवन हमला

1. 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली स्थित संसद भवन पर हमले में 6 पुलिसकर्मियों और 3 संसद कर्मचारियों सहित 9 लोगों की मौत हुए।

2. लेकिन यह हमला इस लिहाज से ज्यादा बड़ा था कि आतंकियों ने लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद को निशाना बनाने का दुस्साहस किया था।

3. पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था।

4. हमले के वक्त उस समय के गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित 100 से ज्यादा एमपी संसद भवन के अंदर मौजूद थे।

1998 कोयंबटूर धमाके

1. 14 फरवरी 1998 को कोयंबटूर में 11 अलग-अलग स्थानों पर 12 बम धमाके हुए।

2. इन धमाकों में मुख्य निशाना भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी थे, जो उस समय एक चुनावी मीटिंग के लिए शहर में थे।

3. ज्यादातर बम शहर के हिंदू बहुल इलाकों में रखे गए थे। इन धमाकों में 60 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा जोल जख्मी हो गए थे।

2001 जम्मू-कश्मीर विधानसभा हमला

1. 1 अक्टूबर 2001 को जैश-ए-मोहम्मद के 3 आत्मघाती आतंकी एक कार बम के साथ श्रीनगर स्थित विधानसभा में घुस गए।

2. इस आतंकी हमले में 38 लोगों की असामयिक मौत हो गई, जबकि तीनों आतंकी भी इस हमले में मारे गए।

2007 समझौता एक्सप्रेस धमाके

1. भारत में दिल्ली और पाकिस्तान में लाहौर के बीच हफ्ते में दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 की रात धमाके हुए।

2. ट्रेन के दो डिब्बों में बम रखे गए थे। दिल्ली से करीब 80 किमी दूर पानीपत के पास दीवाना स्टेशन के पास ट्रेन में यह धमाके हुए।

3. धमाके और आग लगने के कारण 68 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों घायल हो गए। हताहतों में ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे। इस घटना के लिए तश्कर-ए-तैयबा और हिन्दू राष्ट्रवादी संगठनों को जिम्मेदार माना जाता है।

1999 कांधार विमान हाइजेक

1. नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या आईसी 814 को हरकत-उल-मुजाहिद्दिन के आतंकवादियों ने 24 दिसंबर 1999 को हवा में ही हाईजैक कर लिया।

2. आतंकी विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई ले जाने के बाद आतंकवादियों ने विमान को अफगानिस्तान में कांधार हवाई अड्डे पर उतारा। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का राज था।

3. यह बंधक संकट 31 दिसंबर को तीन खूंखार आतंकवादियों मुस्ताक अहमद जर्गर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर की रिहाई के साथ खत्म हुआ।

4. इसमें आतंकियों ने एक यात्री को मार दिया था, जबकि 176 यात्री व 15 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया।

स्पेस में भारत का कमाल

25 साल पहले वर्ष 1992 में स्पेस में भारत की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त चाल चली। क्रायोजेनिक तकनीक के हस्तांतरण पर अमेरिकी प्रशासन ने रूस को स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हालात में वो भारत को तकनीकी मुहैया न कराए। लेकिन भारत ने अमेरिका की चुनौती को स्वीकार किया और क्रायोजेनिक तकनीक का इजाद किया। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अमेरिका जो पहले भारत के खिलाफ आंखें तरेरता था वो नजर अब झुक चुकी है। अमेरिका ने करीब 1.5 बिलियन डॉलर के निसार प्रोजेक्ट पर इसरो के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है।

क्या है

1. 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पैस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, उस समय अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाकर उसे पैस्ट के साथ क्रायोजेनिक इंजन तकनीक साझा करने से भी रोक दिया था।

2. अमेरिका की इन सभी कोशिशों का मकसद भारत को मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने से रोकना था। तमाम प्रतिबंधों और मुश्किलों के बाद भी इसरो ळैस्ट को बनाने में कामयाब रहा।

3. इसमें लगने वाले क्रायोजेनिक इंजन को भारत में ही विकसित किया गया। इसे बनाने की मुश्किलों की वजह से ही शायद इसरो की टीम ळैस्ट को नटखट बच्चा के नाम से पुकारा करती थी।

निसार का सफर

1. इसमें दो फ्रीक्वेंसी की रडार प्रणाली, 13 सेन्टीमीटर का एस बैंड एसएआर और 24 सेमी को एल बैंड एसएआर होगी। एस बैंड एसएआर को इसरो और एल बैंड एसएआर को नासा बना रहा है।

2. डाटा के लिए उच्च गुणवत्ता के संचार का उपतंत्र, जीपीएस रिसीवरस सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर, पेलोड डाटा उपतंत्र नासा उपलब्ध कराएगा।

3. इसरो निसार का मॉडल तय करेगा, जियोसिनक्रोनस सेटेलाइट लॉंच व्हीकल और प्रक्षेपण से जुड़ी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

अभियान है खास

1. निसार की उन्नत रडार प्रणाली एसएआर के जरिए पृथ्वी की विस्तृत और साफ रडार तस्वीरें उपलब्ध हो पाएंगी।

2. पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में फेरबदल, बर्फ क्षेत्र का घटना, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी और भूस्खलन के संबंध में बेहतर जानकारी जुचाई जा सकेगी।

3. इससे पृथ्वी की उपरी परत क्रस्ट की उत्पत्ति, मौसम और पर्यावरण पर विस्तृत शोध हो सकेगा और भविष्य की संसाधनों और खतरों के बारे में पता लगा पाना संभव हो सकेगा। इसके जरिए जलस्रोतों की भी पुख्ता जानकारी मिल सकेगी।

नासा और इसरो का साथ

1. नासा 2007 से पृथ्वी के पारिस्थितकी तंत्र संरचना और बर्फीले स्थानों में होने वाले बदलावों को सिंथेटिक अपर्चर रडार के जरिए मापने की संभावना पर काम कर रहा है।

2. इसी क्रम में नासा ने इसरो से एल बैंड और एस बैंड से लैस एसएआर उपग्रह बनाने के लिए हाथ मिलाया। नासा के मुताबिक इसरो से बेहतरीन इस परियोजना में और कोई बेहतर साझीदार नहीं हो सकता है।

स्पेस में भारत

1. इसरो ने चैस्ट के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट का सफल लॉन्च किया गया है. वैसे अभी तक यह रिकार्ड रूस के नाम है, जो 2014 में 37 सैटेलाइट एक साथ भेजने में कामयाब रहा है.

2. इस लॉन्च में जो 101 छोटे सैटेलाइट्स हैं उनका वजन 664 किलो ग्राम था। इन्हें कुछ वैसे ही अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया जैसे स्कूल बस बच्चों को क्रम से अलग-अलग ठिकानों पर छोड़ती जाती हैं।

3. इसरो ने 1990 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) को विकसित किया था। 1993 में इस यान से पहला उपग्रह ऑर्बिट में भेजा गया, जो भारत के लिए गर्व की बात थी। इससे पहले यह सुविधा केवल रूस के पास थी.

4. 2008 में इसरो ने चंद्रयान बनाकर इतिहास रचा था. 22 अक्टूबर 2008 को स्वदेश निर्मित इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को चांद पर भेजा गया था. इससे पहले ऐसा सिर्फ छह देश ही कर पाए थे।

5. भारतीय मंगलयान ने इसरो को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया. मंगल तक पहुंचने में पहले प्रयास में सफल रहने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसियों को कई प्रयासों के बाद मंगल ग्रह पहुंचने में सफलता मिली। चंद्रयान की सफलता के बाद ये वह कामयाबी थी जिसके बाद भारत की चर्चा अंतराष्ट्रीय स्तर पर होने लगी।

6. जीएसएलवी मार्क 2 का सफल प्रक्षेपण भी भारत के लिए बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इसमें भारत ने अपने ही देश में बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन लगाया था। इसके बाद भारत को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा।

7. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने 28 अप्रैल 2016 भारत का सातवां नेविगेशन उपग्रह (इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) लॉन्च किया। इसके साथ ही भारत को अमेरिका के जीपीएस सिस्टम के समान अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम मिल गया। इससे पहले अमेरिका और रूस ने ही ये उपलब्धी हासिल की थी।

8. इसरो के लिए 2016 रहा अहम -तकनीकी मोर्चे पर इस एक साथ 20 उपग्रह लॉन्च करने के अलावा इसरो ने अपना नाविक सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली स्थापित किया और दोबारा प्रयोग में आने वाले प्रक्षेपण यान (आरएलवी) और स्क्रैमजेट इंजन का सफल प्रयोग किया। इस साल इसरो ने कुल 34 उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में स्थापित किया, जिनमें से 33 उपग्रहों को स्वदेश निर्मित रॉकेट से और एक उपग्रह (जीएसएटी-18) को फ्रांसीसी कंपनी एरियानेस्पेस द्वारा निर्मित रॉकेट से प्रक्षेपित किया. भारतीय रॉकेट से प्रक्षेपित किए गए 33 उपग्रहों में से 22 उपग्रह दूसरे देशों के थे, जबकि शेष 11 उपग्रह इसरो और भारतीय शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्मित थे।

9. 1962 में स्थापना के बाद शुरूआती दौर में जीएसएलवी व पीएसएलवी सीरीज के कुछ उपग्रहों की असफलताओं के बाद से इसरो लगातार सफलताएं हासिल कर रहा है। इसरो ने अपने कारनामों से चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आज अमेरिकी स्पेस संगठन नासा के बाद इसरो दुनिया का सबसे भरोसेमंद स्पेस शोध संस्थान बन गया है।

हर्षवर्धन ने संभाला पर्यावरण मंत्रालय का प्रभार

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने 22 मई को पर्यावरण मंत्रालय का प्रभार ले लिया। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के निधन की वजह से यह पद खाली हो गया था। दवे का 60 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से बीते 18 मई को निधन हो गया था। इसके बाद सरकार ने विज्ञान एवं तकनीक मंत्री हर्षवर्धन को पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया।

क्या है

1. प्रभार लेने के बाद हर्षवर्धन ने दवे की स्मृति में मंत्रालय परिसर में एक पौधा लगाया। दवे ने अपनी वसीयत में लिखा था कि अगर आप मेरी यादों को जिंदा रखना चाहते हैं तो पौधारोपण करें। उन्होंने जोर देकर कहा था कि वह अपने नाम पर कोई प्रतिमा, स्मारक या कोई पुरस्कार नहीं चाहते। दवे जीएम सरसों पर अंतिम फैसला लेने वाले थे।

2. मंत्रालय की संस्था दि जनेटिक इंजिनियरिंग अप्रेजल कमिटी आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों का आकलन करती है।

3. इस संस्था ने 11 मई को जीएम सरसों के व्यावसायिक इस्तेमाल की सिफारिश भेजी थी। इसके बाद, इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने का जिम्मा पर्यावरण मंत्री को सौंप दिया गया था।

देश में पहली बार होगा हाथी के आंखों का ऑपरेशन

देश में पहली बार एक हथिनी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। जयपुर में पर्यटकों में लोकप्रिय 44 साल की लक्ष्मी को मोतियाबिंद की शिकायत है। जिसके ऑपरेशन के लिए मेडिकल टीम गठित कर दी गई है। जयपुर के प्रमुख पर्यटक स्थल आमेर में पर्यटकों को घुमाने वाली 44 वर्षीय हथिनी श्लक्ष्मीश की आंख में पिछले छह महीने से मोतियाबिंद की शिकायत है। इसका इलाज भी चल रहा है। लेकिन अब इसका ऑपरेशन करने का निर्णय किया गया है।

क्या है

1. राज्य सरकार के अलावा वन विभाग एवं पशु चिकित्सा विभाग का दावा है कि देश में पहली बार किसी हाथी के आंख का ऑपरेशन किया जा रहा है।

2. राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का कहना है कि अपनी तरह की यह पहली सर्जरी होगी। इसके लिए हथिनी के मालिक अब्दुल अजीज की रजामंदी ली गई है।

3. पशु चिकित्सा विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञों की मेडिकल टीम ने कुछ जांच भी कराई है। अब अगले कुछ दिनों में जयपुर के नाहरग़ढ बायोलॉजिकल पार्क के वन्यजीव अस्पताल में हथिनी की आंख की सर्जरी की जाएगी।

4. चिकित्सकों का दावा है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हथिनी पहले की तरह देख सकेगी।

मिला एलियन का संकेत

वैज्ञानिकों ने धरती से महज 21 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक सुपर अर्थ की खोज की है। धरती से मिलते-जुलते इस ग्रह पर जीवन के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर पानी उपलब्ध है।

वैज्ञानिकों ने रेडियल वेलोसिटी तकनीक की मदद से इस ग्रह की जानकारी जुटाई है।

क्या है

1. इस ग्रह का द्रव्यमान धरती से दो से तीन गुना तक है। यह अपने तारे जीजे-625 से ऐसी दूरी पर है, जो जीवन के योग्य मानी जाती है। हमारे सौरमंडल के नजदीक यह ऐसा छठा सुपर अर्थ है, जो अपने ग्रह से इस तरह की दूरी पर है।

2. इसका तारा रेड ड्वार्फ की श्रेणी का है। ये ऐसे तारे होते हैं, जिनके इर्द-गिर्द ग्रह हो सकते हैं। अब तक ऐसे कुछ सौ तारे पहचाने जा सके हैं।

3. श्जीजे-625 अपेक्षाकृत ठंडा तारा है। खोजा गया ग्रह इससे ऐसी दूरी पर है जहां पानी तरल रूप में रह सकता है। इसके पर्यावरण और घूमने की गति सही हुई तो इस पर जीवन संभव है।श

प्ब्ब वनडे रैंकिंग में अकेले भारतीय

भारतीय कप्तान विराट कोहली देश के अकेले क्रिकेटर हैं जो आईसीसी वनडे खिलाड़ियों की रैंकिंग में टॉप दस में शामिल हैं। उन्होंने बल्लेबाजों की सूची में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। व्यक्तिगत रैंकिंग के लिये कड़ी टक्कर से (आने वाली) आईसीसी चौंपियन्स ट्रॉफी के महत्व का पता चलता है क्योंकि इसमें भाग लेने वाले आठ टीमों के खिलाड़ी इसमें शामिल हैं और टॉप खिलाड़ियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है।

चोटी के तीन बल्लेबाजों दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (874 रेटिंग अंक), ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर (871 अंक) और कोहली (852 अंक) के बीच केवल 22 अंक का अंतर है।

क्या है

1. बल्लेबाजों की सूची में टॉप 20 में रोहित शर्मा (12वें), महेंद्र सिंह धौनी (13वें) और शिखर धवन (15वें) नंबर पर शामिल हैं। धवन दो पायदान नीचे खिसके हैं।

2. गेंदबाजों की सूची में हालांकि कोई भारतीय टॉप दस में शामिल नहीं है। इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबादा शीर्ष पर काबिज हैं। बायें हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल न्यूजीलैंड के मैट हेनरी के साथ संयुक्त 11वें जबकि अमित मिश्रा 13वें स्थान पर हैं। ये दोनों ही चौंपियन्स ट्राफी के लिये भारतीय टीम में शामिल नहीं हैं। रविचंद्रन अश्विन संयुक्त 18वें स्थान पर हैं।

3. चोटी के तीन गेंदबाजों रबादा (724 अंक), इमरान ताहिर (722) और मिशेल स्टार्क (701) के बीच केवल 23 अंकों का अंतर है।

4. भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के चार-चार बल्लेबाज जबकि न्यूजीलैंड के तीन तथा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दो-दो बल्लेबाज टॉप 20 में शामिल हैं।

5. इसी तरह से गेंदबाजों में बांग्लादेश और इंग्लैंड के तीन-तीन जबकि न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दो-दो गेंदबाज टॉप 20 में शामिल हैं।

6. ऑलराउंडरों की सूची में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन शीर्ष पर काबिज हैं। इंग्लैंड के तीन खिलाड़ी इस सूची में शीर्ष दस में शामिल हैं।

7. इंग्लैंड को दक्षिण अफ्रीका पर श्रंखला में जीत से दो अंकों का फायदा हुआ। टीम रैंकिंग में भी चोटी की टीमों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है और इससे पता चलता है कि चौंपियन्स ट्राफी में मुकाबला काफी कड़ा होगा।

8. वनडे की चोटी की पांच टीमों में दक्षिण अफ्रीका (122 अंक), ऑस्ट्रेलिया (118), भरत (117), न्यूजीलैंड (114) और इंग्लैंड (112) के बीच अधिक अंतर नहीं है और वे एक दूसरे को पीछे छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

9. दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड पहले भी इस प्रतिष्ठित टूनार्मेंट को जीत चुके हैं जबकि पिछली बार फाइनल में पहुंचने वाला इंग्लैंड इस बार अपनी घरेलू परिस्थितियों में खिताब जीतने की कोशिश करेगा।

10. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रंखला में जीत से उसका मनोबल बढ़ा है। एक से 18 जून तक चलने वाले टूनार्मेंट में बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमों को टीम रैंकिंग में अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा क्योंकि इंग्लैंड तथा सात अन्य चोटी की टीमों को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सीधा प्रवेश मिलेगा।

आसमान से खिंचेगी धरती की एचडी फोटो

ब्रिटेन की एक कंपनी आसमान से धरती की उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी उपग्रहों का एक नेटवर्क लांच करेगी। इसकी मदद से धरती की रंगीन तस्वीरें ली जा सकेंगी और किसी भी वाहन को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा।

क्या है

1. कंपनी अर्थ-आइ परीक्षण के तौर पर इसका प्रोटोटाइप इस साल के आखिर तक लांच करेगी। इसके बाद 2019 तक पांच और प्रक्षेपण किए जाएंगे। इन उपग्रहों की मदद से बेहद तेजी से स्पष्ट तस्वीरें खींचना संभव होगा।

2. ब्रिटिश कंपनी सरे सेटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड (एसएसटीएल) ने इस नई श्रेणी के उपग्रहों को तैयार किया है। इन्हें कार्बोनाइट नाम दिया गया है।

3. इस श्रेणी का पहला उपग्रह सिर्फ छह महीने में तैयार करके 2015 में प्रक्षेपित किया गया था। पहले प्रक्षेपण के अनुभवों के आधार पर वैज्ञानिकों ने नए उपग्रह तैयार किए हैं।

4. अर्थ-आइ के सीईओ रिचर्ड ब्लेन ने कहा, श्हमने एसएसटीएल के साथ कार्बोनाइट-1 पर काम किया था और इसके प्रदर्शन का अध्ययन कर कार्बोनाइट-2 के विकास में तकनीकी सहयोग किया।श

दुनिया का पहला श्लेपर्ड रिजर्वश

दुनिया का पहला श्लेपर्ड रिजर्वश जयपुर के झालाना वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। अभी झालाना वन क्षेत्र में करीब डेढ़ दर्जन लेपर्ड हैं। राज्य सरकार ने अपने बजट में इसके लिए खास वित्तीय प्रबंध किए हैं जिससे इस दिशा में कार्य तेज हो गया है।

क्या है

1. राज्य के वन मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इसे दुनिया का पहला लेपर्ड रिजर्व बताया है। उन्होंने कहा कि इसे विकसित करने के लिए वन्य जीव विशेषज्ञों और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की गई है।

2. उनका दावा है कि करीब एक वर्ष पूर्व ही इसे विकसित करने को लेकर सरकार ने योजना बनाई थी। इसके तहत देश-विदेश के कुछ अन्य लेपर्ड पार्को का अध्ययन किया गया। इसके बाद जयपुर के झालाना पार्क में दुनिया का पहला लेपर्ड रिजर्व बनाने का निर्णय लिया गया।

3. गौरतलब है कि जयपुर शहर के निकट होने के कारण झालाना वन क्षेत्र से निकलकर कई बार लेपर्ड रिहायशी क्षेत्रों या आम रास्तों तक पहुंच जाते हैं। अब इनकी सुरक्षा के लिए झालाना वन क्षेत्र के चारों ओर दीवार बनाने के साथ ही अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को पहले चरण में तो झालाना वन क्षेत्र में चलाया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्लोवाकिया के विदेश मंत्री मिरोस्लाव लैजकक को 193 सदस्यीय शक्तिशाली निकाय का अगला अध्यक्ष चुना। विशेष सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें सत्र के लिए लैजकक (54) को ध्वनि मत से अध्यक्ष चुन लिया गया।

क्या है

1. पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के उम्मीदवारों में से एक लैजकक फिजी के राजनयिक पीटर थॉमसन का स्थान लेंगे।

2. अपने निर्वाचन के बाद स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री ट्वीट कर संयुक्त राष्ट्र महासभा को धन्यवाद दिया और दुनिया को रहने के लिहाज से बेहतर बनाने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता प्रकट की।

3. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरेस ने लैजकक को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है।

अर्थशास्त्र

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

खेल

विविध